

बाह्य क्षेत्रः एफडीआई को व्यवस्थित रूप देना

आर्थिक और व्यापार संबंधी नीतिगत अनिश्चितताओं की वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के बाह्य क्षेत्र ने लचीलापन प्रदर्शित करना जारी रखा। वित्त वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों में कुल निर्यात (माल और सेवाएँ) में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, जो 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (6 प्रतिशत) तक पहुँच गया है। पेट्रोलियम और रत्न एवं आभूषणों को छोड़कर सेवाओं और माल निर्यात में वृद्धि 10.4 प्रतिशत थी। इसी अवधि के दौरान कुल आयात स्थिर घरेलू मांग के कारण 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 682.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।

विकसित हो रही वैश्विक व्यापार गतिशीलता, जो अधिक संरक्षणवाद की ओर क्रमिक बदलावों से चिह्नित है, के लिए स्थिति का आकलन करने और एक दूरदर्शी रणनीतिक व्यापार रोडमैप विकसित करने की आवश्यकता है। इन रुझानों को अपनाकर और अपनी क्षमता का लाभ उठाकर, भारत अपने विकास को गति दे सकता है और वैश्विक व्यापार में अपनी उपस्थिति बढ़ा सकता है। अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं से और अधिक जुड़ने के लिए देश व्यापार से संबंधित लागतों को कम करने और निर्यात सुविधा को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है ताकि एक अधिक जीवंत निर्यात क्षेत्र बनाया जा सके। यह सक्रिय दृष्टिकोण भारत को निरंतर बदलते वैश्विक बाजार में आगे बढ़ने में मदद करेगा।

पूँजी के मोर्चे पर, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) ने वित्त वर्ष 25 में अब तक मिश्रित रुझान दिखाया है। वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा मुनाफाकावसूली के कारण पूँजी बहिर्प्रवाह हुआ। हालांकि, मजबूत वृहद आर्थिक बुनियादी बातों, अनुकूल कारोबारी माहौल और उच्च आर्थिक विकास ने एफपीआई अंतर्वाह को समग्र रूप से सकारात्मक बनाए रखा है। सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह ने वित्त वर्ष 25 के पहले आठ महीनों में पुनरुद्धार के संकेत दिखाए हैं, तथापि, प्रत्यावर्तन/विनिवेश में वृद्धि के कारण अप्रैल-नवंबर 2023 के सापेक्ष निवल एफडीआई प्रवाह में गिरावट आई है।

दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो सितंबर 2024 तक देश के 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लगभग 90 प्रतिशत विदेशी ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त था, जो बाहरी कमजोरियों के खिलाफ एक मजबूत बफर को दर्शाता है।

परिचय

3.1 भू-राजनीतिक संघर्षों, भू-आर्थिक विखंडन की बढ़ती प्रवृत्तियों और बार-बार होने वाले जलवायु संबंधी घटनाओं के कारण दुनिया बढ़ती हुई राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता का अनुभव कर रही है। 2024 का महान चुनावी वर्ष, जिसके दौरान दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी अपनी नई सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही थी, यानि नीतिगत पूर्वानुमान में और भी देरी। ऐसी राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता विकास में बाधा बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान है कि अनिश्चितता में एक मानक विचलन की वृद्धि से उत्पादन वृद्धि¹ में 0.4 से 1.3 प्रतिशत की कमी आती है। कीन्स और टोबिन जैसे अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि उच्च अनिश्चितता के कारण निवेशकों को जोखिमों के लिए अधिक मुआवजे की मांग करनी पड़ती है, जिससे जोखिम प्रीमियम और वित्त की समग्र लागत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त, अनिश्चितता के कारण उधारकर्ताओं द्वारा ऋण न चुकाने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे पूँजी लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा, अमेरिका जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के कारण अक्सर उत्पादन कम होता है और कीमतें कम² हो जाती हैं।

3.2 वैश्विक जोखिमों और अनिश्चितताओं को मॉनिटर करने तथा वैश्विक आर्थिक गतिविधि पर नीति-संबंधी अनिश्चितता के प्रभाव को मापने के लिए विभिन्न संकेतकों का उपयोग किया जाता है। इनमें भू-राजनीतिक जोखिम (जीपीआर) सूचकांक³ शामिल है, जो समाचार-पत्रों के लेखों के माध्यम से प्रतिकूल भू-राजनीतिक घटनाओं पर नजर रखता है; व्यापार नीति अनिश्चितता (टीपीयू) सूचकांक⁴, जिसके अंतर्गत व्यापार नीति अनिश्चितता और बढ़े हुए व्यापार तनावों का उल्लेख करने वाले लेखों की आवृत्ति शामिल है, और वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता (जीईपीयू) सूचकांक⁵, जो 21 देशों के लिए राष्ट्रीय आर्थिक नीति अनिश्चितता (ईपीयू) सूचकांकों का जीडीपी-भारित औसत है। ये सूचकांक अर्थव्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाते हैं, जो वैश्विक उत्पादन⁶ का लगभग 71 प्रतिशत हिस्सा हैं।

3.3 ये सूचकांक इस बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं कि व्यापार मुद्दों, भू-राजनीतिक घटनाओं और आर्थिक नीति उपायों से अनिश्चितता वैश्विक आर्थिक स्थितियों को कैसे प्रभावित कर सकती है। नवंबर 2024 तक, 'जीईपीयू सूचकांक' उच्च बना हुआ है, जो विद्यमान वैश्विक आर्थिक नीतिगत मामलों को दर्शाता है। इसी तरह, दिसंबर 2023 से टीपीयू सूचकांक में वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार तनावों और नीतिगत परिवर्तनों से प्रेरित है।

1 डॉटलिंग, आर., मलाइका, एम., एंड टेरोनेस, एम. (2013)। हेल्ड बैक बाई अनसटैटी: रिकवरीज आर स्लोव्ड व्हेन बिजनेस एंड कंज्यूमर्स आर अनस्योर ऑफ द फ्यूचर फाइनेंस - डेवलपमेंट,, 0050(001), A012. <https://tinyurl.com/324z5ux4>.

2 लेडुक, एस., और लियू, जे.ड. (2016)। अनसटैटी शॉक्स आर एग्रीगेट डिमांड शॉक्स। जर्नल ऑफ मॉनेटरी इकोनोमिक्स, 82, 20-35; कुमार, ए., मलिक, एस., एंड सिन्हा, ए. (2021)। इज अनसटैटी द सेम एकरीच्येर? एडवांस्ड वर्सस एमर्जिंग इकोनोमीज. इकोनोमिक मॉडलिंग101, 105524, <https://tinyurl.com/6n74paw2>.

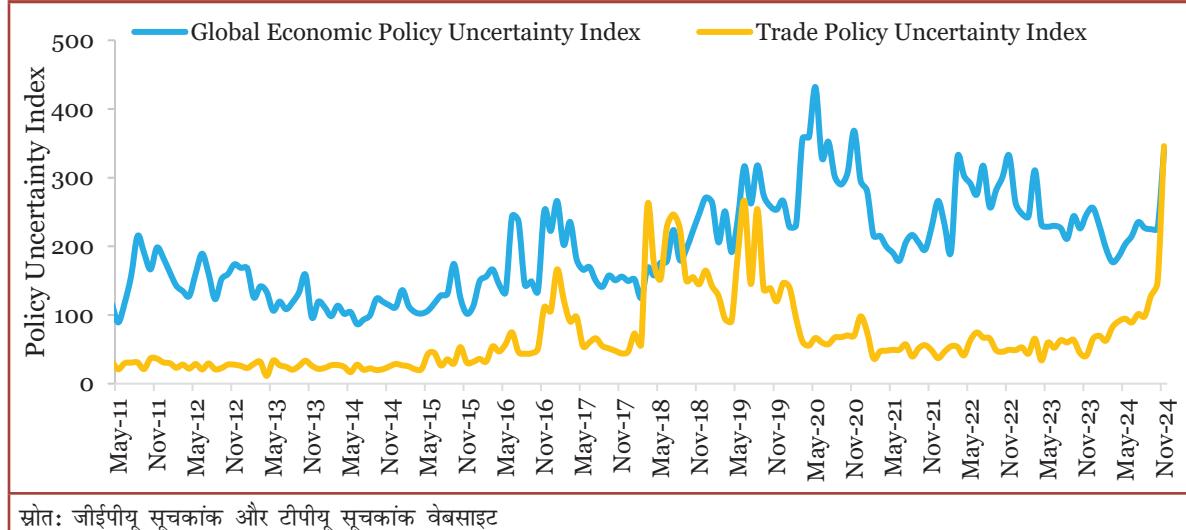
3 जियोपोलिटिकल रिस्क इंडेक्स, <https://www.policyuncertainty.com/gpr.html>.

4 ट्रेड पॉलिसी अनसटैटी इंडेक्स, <https://www.matteoiacoviello.com/tpu.htm>.

5 ग्लोबल इकोनोमिक पॉलिसी अनसटैटी इंडेक्स, <https://www.policyuncertainty.com/>.

6 वैश्विक उत्पादन की गणना क्रय शक्ति समता के आधार पर की जाती है। यदि अर्थव्यवस्थाओं को बाजार विनिमय दरों पर गिना जाए तो अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं।

चार्ट III.1: वैश्विक अनिश्चितता में वृद्धि



3.4 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न वैश्विक सूचकांकों का उपयोग करते हुए विशेष रूप से भारत के लिए एक नीतिगत अनिश्चितता सूचकांक विकसित किया है। यह सूचकांक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से नीति अनिश्चितता का आकलन करने के लिए 'गूगल ट्रैंड्स' से इंटरनेट सर्च डेटा का लाभ उठाता है। इसके अलावा, सूचकांक को वास्तविक समय(रियल टाइम)^{7,8} में अपडेट किया जाता है।

3.5 इस पृष्ठभूमि के साथ, यह अध्याय मौजूदा वैश्विक परिवेश के बीच भारत के बाह्य क्षेत्र के प्रदर्शन को प्रस्तुत करता है। खंड-I में वैश्विक व्यापार गतिशीलता का विवरण है, जिसमें टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों (एनटीएम) और चुनौतियों के बीच वैश्विक वैदेशिक क्षेत्र के कार्य निष्पादन पर बल दिया गया है। खंड-II में भारत के व्यापार निष्पादन पर गहनता से चर्चा की गई है, जिसमें वस्तु और सेवा दोनों क्षेत्रों में रुझानों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें भारत के कपड़ा निर्यात के कार्य निष्पादन और इसके वैश्विक विस्तार को बाधित करने वाले कारकों की जांच की गई है। इसके अलावा, नए बाजारों में भारत के निर्यात विविधीकरण का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। भारत के ई-कॉमर्स निर्यात वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख चालकों और चुनौतियों पर भी गहराई से चर्चा की गई है। खंड III में निर्यात वृद्धि को बाधित करने वाले कारकों पर चर्चा की गई है और व्यापार निष्पादन को बढ़ाने के संबंध में निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सरकार की पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। खंड IV में भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी)) की स्थिति प्रस्तुत की गई है, जिसमें चालू खाता और पूंजी खाता प्रवृत्तियों, विदेशी मुद्रा भंडार, विनिमय दर की गतिविधियों और भारत की विदेशी ऋण स्थिति पर प्रकाश

7 जब अत्यधिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, तो आर्थिक एजेंटों के लिए अधिक जानकारी की 'खोज' करना आम बात है। द गूगल ट्रैंड्स-बेस्ड अनसटेटी इंडेक्स (ईडिया-जीयूरे) भारत में राजकोषीय, मौद्रिक और व्यापार नीति के बारे में कीवर्ड की सूची के लिए इंटरनेट खोज मात्रा का उपयोग करके समग्र अनिश्चितता को मापने के लिए इस व्यवहार का लाभ उठाता है। नीति-संबंधी कीवर्ड केंद्रीय बैंक नीति वक्तव्यों में उल्लेखों के साथ-साथ वित्तीय प्रेस में कवरेज के आधार पर तैयार किए जाते हैं। प्रताप, बी., एंड प्रियरंजन, एन. (2023)। मैक्रोइकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ अनसटेटी: ए गूगल ट्रैंड्स-बेस्ड एनालिसिस फोर इडिया. एम्परिकल इकोनॉमिक्स, 65(4), 1599-1625, <https://tinyurl.com/5fb373we>.

8 विचलन से अभिसरण की ओर पुनर्जनना: भारतीय अनुभव - माइकल देबब्रत पत्रा, डेप्यूटी गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया उद्घाटन भाष - अक्टूबर 21, 2024 - फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित न्यूयॉर्क फेड सेंट्रल बैंकिंग सेमिनार, न्यू यॉर्क, यूएस, <https://tinyurl.com/mvajhcj7>.

डाला गया है। अंतिम खंड में उभरते वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य पर विचार करते हुए भारत के वैदेशिक क्षेत्र के दृष्टिकोण के साथ अध्याय का समापन किया गया है।

वैश्विक व्यापार गतिशीलता

3.6 नवंबर 2023 में लाल सागर में शुरू हुए व्यवधानों ने व्यापार मार्गों में परिवर्तन करने पर मजबूर कर दिया, जिससे नौ-परिवहन लागत बढ़ गई है और सुपुर्दगी का समय⁹ भी लंबा हो गया है। यह बात एशिया और यूरोप के बीच व्यापार के लिए विशेष रूप से सत्य है, क्योंकि इस व्यापार का 40 प्रतिशत भाग लाल सागर क्षेत्र¹⁰ से होकर गुजरता है। होरमज स्ट्रेट में इसी तरह के ढंगों ने ऊर्जा व्यापार को बाधित किया है और कीमतों में वृद्धि की है, जो वैश्विक पेट्रोलियम तरल खपत का 21 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन अनिश्चितताओं¹¹ को बढ़ा रहा है। उदाहरण के लिए, पनामा नहर में हाल ही में पड़े सूखे ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को खतरे में डाल दिया, जिससे इस नहर से होकर गुजरने वाले वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 5 प्रतिशत प्रभावित हुआ। ये स्थितियाँ अनिश्चितता पैदा कर रही हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मंदी आ रही है,¹² संरक्षणवादी व्यापार नीतियों में वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव के रूप में व्यापार की रूपरेखा को नया आकार दे रहे हैं।

3.7 जैसा कि चार्ट III.2 से स्पष्ट है, वर्ष 2022 के अंत से व्यापार की राजनीतिक निकटता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह समान भू-राजनीतिक रुख वाले देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार के लिए प्राथमिकता को दर्शाता है, यानी फ्रेंड शोरिंग¹³ और नियरशोरिंग।¹⁴ समर्वर्ती रूप से, महत्वपूर्ण व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार¹⁵ का संकेन्द्रण बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, हाल के वर्षों में यूरोपीय संघ पर रूस और चीन की व्यापार निर्भरता और चीन पर अमेरिका की निर्भरता में गिरावट आई है। इसके विपरीत रूस और वियतनाम की चीन पर निर्भरता बढ़ गई है।^{16,17}

9 यूएनसीटीएडी रेपिड असेसमेंट, 'इम्पैक्ट टू ग्लोबल ट्रेड ऑफ डिसरेशन ऑफ शिपिंग रुट्स इन द रेड सी, ब्लैक सी एंड पनामा कैनल', https://unctad.org/system/files/official-document/osginf2024d2_en.pdf.

10 बोनेल और मैकडू, 2024, <https://tinyurl.com/5n7wy8xj>.

11 अमेरिकी, एनर्जी इनफार्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, <https://www.eia.gov/>.

12 आईएमएफ वर्किंग ऐपर दिनांक 9 जुलाई 2024, 'द हेटरोजेनस इफेक्ट्स ऑफ अनसर्टेटी ओन ट्रेड', <https://tinyurl.com/2xywd48v>.

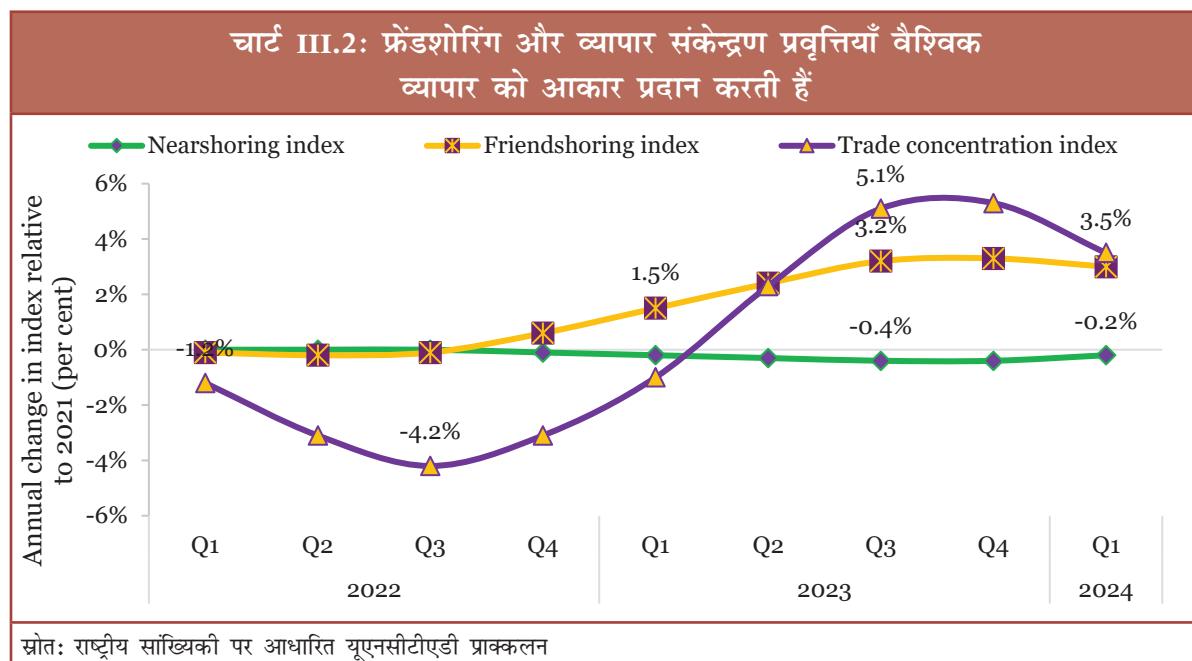
13 फ्रेंड शोरिंग की गणना व्यापार-भारित राजनीतिक निकटता के रूप में की जाती है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के मतदान पैटर्न द्वारा मापा जाता है।

14 नियरशोरिंग की गणना किलोमीटर में व्यापार-भारित औसत दूरी के विपरीत की जाती है।

15 व्यापार संकेन्द्रण की गणना हर्फिडाहल संकेन्द्रण सूचकांक के आधार पर की गई है।

16 यूएनसीटीएडी एस्टीमेट्स बेस्ड ऑन नेशनल स्टैटिस्टिक्स (<https://unctad.org/statistics>) एक अर्थव्यवस्था की दूसरी अर्थव्यवस्था पर निर्भरता की गणना आश्रित अर्थव्यवस्था के कुल व्यापार पर उनके द्विपक्षीय व्यापार के अनुपात के रूप में की जाती है। वार्षिक परिवर्तन की गणना पिछली चार तिमाहियों में व्यापार-भारित चल औसत का उपयोग करके की जाती है।

17 यूएनसीटीएडी ग्लोबल ट्रेड अपडेट, जुलाई 2024, <https://tinyurl.com/uwputbfs>.



3.8 एनटीएम सहित सरकारी अंतःक्षेप, ‘भू-राजनीतिक विचारों’ के कारण द्विपक्षीय व्यापार पैटर्न में बदलाव को मजबूत करते हैं। गैर-टैरिफ उपायों (एनटीएम) में वृद्धि, जो कोविड-19 महामारी के बाद शुरू हुई, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के कारण और बढ़ गई। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)¹⁸ की एक रिपोर्ट बताती है कि तकनीकी एनटीएम 30 प्रतिशत से अधिक उत्पादों और लगभग 70 प्रतिशत वैश्विक व्यापार को प्रभावित करते हैं। इस अध्याय के पैरा 3.15 से 3.20 में इस पर आगे चर्चा की गई है।

2024 में वैश्विक व्यापार निष्पादन

3.9 यू.एन.सी.टी.ए.डी.¹⁹ के नवीनतम व्यापार अपडेट के अनुसार, 2023 की दूसरी छमाही में शुरू हुई वैश्विक व्यापार में क्रमिक वृद्धि वर्ष 2024 तक जारी रही। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) डेटाबेस 2024 की तीसरी तिमाही में वैश्विक माल निर्यात और आयात सूचकांकों में क्रमशः 3.5 प्रतिशत और 3 प्रतिशत की साल-दर-साल (YoY) वृद्धि दर्शाता है (मौसमी रूप से समायोजित, 2005 Q1=100)। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान वैश्विक सेवा निर्यात और आयात में 7.9 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत (YoY) की वृद्धि हुई।

¹⁸ UNCTAD report, ‘Tariff trends mostly downward, but non-tariff measures increasingly used’, <https://sdgpulse.unctad.org/trade-barriers>.

¹⁹ यूएनसीटीएडी ग्लोबल ट्रेड अपडेट, दिसंबर 2024, <https://unctad.org/publication/global-trade-update-december-2024>.

3.10 पिछली चार तिमाहियों में, विकासशील देशों में व्यापार वृद्धि आम तौर पर विकसित देशों से अधिक रही है। हालाँकि, 2024 की तीसरी तिमाही में यह प्रवृत्ति उलट गई, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सकारात्मक विकास ने व्यापार वृद्धि को बढ़ावा दिया। इसके विपरीत, पूर्वी एशिया में व्यापार वृद्धि रुक गई, और कई प्रमुख एशियाई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने नकारात्मक वृद्धि का अनुभव किया।



3.11 यूएनसीटीएडी के नाउकास्ट²⁰ के अनुसार, 2024 की पहली तीन तिमाहियों में वैश्वक व्यापार में देखी गई सकारात्मक गति चौथी तिमाही में भी जारी रहने की उम्मीद है। परिणामस्वरूप, वैश्वक व्यापार 2022 के अपने रिकॉर्ड को पार कर जाएगा, जो 2024 में लगभग 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा। रिकॉर्ड में यह वृद्धि सेवा व्यापार (वर्ष दर वर्ष) में 7 प्रतिशत की वृद्धि के कारण होने की संभावना है, जबकि माल व्यापार 2024 में लगभग 2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, लेकिन 2022 के अपने शिखर से नीचे रहेगा। कुल मिलाकर, 2024 में वैश्वक व्यापार में लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (या 3.3 प्रतिशत) की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का योगदान लगभग 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा।

टैरिफ नीतियाँ

3.12 मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश को प्रोत्साहित करने और व्यापार लागत को कम करने के लिए, दुनिया भर के देशों ने विभिन्न व्यावसायिक करार किए हैं। प्रभावी क्षेत्रीय व्यापार करारों (आरटीए) की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जो 1990 में 22 से बढ़कर अगस्त 2024 तक 369 हो गई है²¹ डब्ल्यूटीओ के तहत मुक्त व्यापार पर बढ़ते जोर और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियों में बढ़ते हुए सहयोग से देशों के बीच सीमा शुल्क में कमी आई है। उदाहरण के लिए, 2000 से 2024 के बीच भारत में शुल्क योग्य मदों पर औसत टैरिफ दरें 48.9 प्रतिशत से घटकर 17.3 प्रतिशत हो गई, जबकि चीन में वे 16.4 प्रतिशत से घटकर 8.3 प्रतिशत हो गई²² वस्तु-वार, 2012 और 2022 के बीच, कृषि, विनिर्माण और

20 उपयुक्त नोट 19.

21 डब्ल्यूटीओ डेटा ओन रिजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, <https://tinyurl.com/59e3yw6b>.

22 बेस्ट ओन द डेटा अवेलेबल ओन द डब्ल्यूटीओ इंटीग्रेटिड डेटाबेस, <https://tao.wto.org/>

प्राकृतिक संसाधनों में सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) और अधिमान्य टैरिफ में गिरावट आई है। वैश्विक स्तर पर, 2012 और 2022 के बीच कृषि के लिए साधारण औसत एमएफएन और अधिमान्य टैरिफ में क्रमशः लगभग 3 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत की गिरावट आई है। विनिर्माण क्षेत्र में सामान्य औसत अधिमान्य टैरिफ में लगभग 1 प्रतिशत की कमी आई है।

3.13 व्यापक स्तर पर, भारत की आयात शुल्क नीति समय के साथ विकसित हुई है, जिसमें घरेलू नीतिगत लक्ष्यों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में समन्वित करने की आवश्यकता के साथ संतुलित किया गया है। टैरिफ क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होते हैं, जिसमें विदेशी प्रतिस्पर्धा से संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं तक पहुँच की अनुमति जैसे पहलू शामिल होते हैं। भारत ने सुनिश्चित किया है कि टैरिफ नीतियाँ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों और विनियमों का अनुपालन करती हैं। समय के साथ, टैरिफ को और अधिक तर्कसंगत बनाने और 'उत्क्रमी शुल्क संरचना' का समाधान करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं।

3.14 प्रायः यह देखा गया है कि टैरिफ का प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ता है। तथापि, यदि इनका उपयोग सही तरीके से किया जाए, तो टैरिफ औद्योगिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं और अर्थव्यवस्था में बांछनीय क्षेत्रों के विकास में मदद कर सकते हैं (बॉक्स III.1)

बॉक्स III.1: टैरिफ और सफल औद्योगिक नीति रूपरेखा

औद्योगिक नीति से तात्पर्य ऐसे उपायों से है जो सार्वजनिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी उद्योग के परिवर्तन को लक्षित करते हैं। टैरिफ औद्योगिक नीति का एक मानक उपकरण है और इसे अक्सर नवोदित उद्योगों को समर्थन देने के रूप में देखा जाता है इससे पहले कि वे गति पकड़ें। तथापि, टैरिफ का उपयोग करने के लिए एक सुविचारित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो क्षेत्र की आवश्यकताओं और शेष अर्थव्यवस्था पर अधिरोपित लागतों में संतुलन पैदा करता है। टैरिफ को साधन युक्त प्रणाली के भीतर एक प्रेरक के रूप में भी देखा जा सकता है जो औद्योगिकीकरण के लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकता है।

औद्योगिक नीति में टैरिफ के उपयोग का पता औद्योगिक क्रांति से लगाया जा सकता है। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति तक पहुँच कायम करने के लिए पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में टैरिफ का इस्तेमाल आम तौर पर किया जाता था। जैसा कि मैथ्यू सी. क्लेन और माइकल पेटिस ने अपनी पुस्तक 'ट्रेड वॉर्स आर क्लास वॉर्स' में उल्लेख किया है।

"फ्रेडरिक लिस्ट जो 1825 में जर्मनी से अमेरिका चले गए थे, ने लिखा था कि जर्मनी जैसा देश, जो कम विकसित था लेकिन उसके पास समृद्ध बनने के लिए "मानसिक और भौतिक साधन" हैं, उसे मुक्त व्यापार से बचना चाहिए और "अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को मजबूत करना चाहिए।" ... संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1870 से 1913 तक निर्मित वस्तुओं पर लगभग 45 प्रतिशत टैरिफ लगाया... अमेरिकी निर्माताओं को विदेशियों से सुरक्षा दी गई लेकिन उन्होंने बड़े और विस्तारित- घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा की।"

यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के विकास के इतिहास पर प्रोफेसर रॉबर्ट सी. एलन द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुरूप है।²³ उनके अनुसार, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी महाद्वीपीय यूरोप ने निम्नलिखित को अपनाकर ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति तक पहुँच बनाई:

23 2013 गिदेन रेसेनब्ल्थ मेमोरियल लेक्चर डॉ रॉबर्ट एलन द्वारा दिया गया, कनाडाई सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्स, <https://tinyurl.com/7cv2hzu6>.

- आंतरिक मुक्त बाजार (आंतरिक शुल्कों का उन्मूलन)-राष्ट्रीय एकल बाजार
- स्थिर घरेलू बैंकिंग प्रणाली
- उच्च बाह्य टैरिफ
- सार्वभौमिक शिक्षा
- अवसंरचना।

मुक्त व्यापार और खुले पूँजी बाजार की बात करें तो वे ब्रिटेन की बराबरी नहीं कर सके।

विश्व स्तर पर, आधुनिक समय की औद्योगिक नीतियां मिश्रित नीतियों का उपयोग करती हैं, जिनमें टैरिफ-आधारित सुरक्षा और क्रेडिट अनुदान और निर्यात-संबंधी सब्सिडी जैसे अन्य प्रेरक (लीवर) शामिल हैं।²⁴ इस तथ्य का उदाहरण देते हुए, 2010 और 2022 के बीच सभी औद्योगिक नीतिगत हस्तक्षेपों में टैरिफ का हिस्सा केवल 1.3 प्रतिशत था।²⁵

सफल औद्योगिक नीति की रूपरेखा की सीख सत्तर के दशक में कोरियाई सरकार द्वारा अपने भारी रसायन उद्योग को दिए गए समर्थन से ली जा सकती है। भारी रसायन के क्षेत्र में कोरियाई औद्योगिक नीति ने उत्पादन, श्रम उत्पादकता और उद्योग के निर्यात के दीर्घकालिक तुलनात्मक लाभ में महत्वपूर्ण लाभ अर्जित किया। टैरिफ-आधारित संरक्षण और मात्रात्मक प्रतिबंध जैसे उपकरणों का उपयोग सीमित अवधि के लिए किया गया था, जिसके बाद 1980 के दशक में संरक्षण कम हो गया।²⁶ महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरिया में टैरिफ समग्र औद्योगिक नीति का केवल एक तत्व था, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योग की रक्षा करना था और साथ ही, संरक्षण प्राप्त करने वाले उद्योग की ओर से पारस्परिक कार्य निष्पादन दायित्व की मांग करना था। सफल औद्योगिक नीति का मूलमन्त्र समर्थन और प्रतिबंधों के एक साथ उपयोग में निहित है, जिसमें प्रतिबंध अक्सर समर्थन से अधिक होते हैं। पूर्वोत्तर एशिया की औद्योगिक नीतियों पर एक व्यापक नजर डालते हुए, जो स्टडवेल ने 'हाउ एशिया वर्क्स' में लिखा है कि यह क्षेत्र अपनी औद्योगिक नीति के साथ सफल रहा क्योंकि इसने निष्पादकों को पुरस्कृत करने की तुलना में गैर-निष्पादकों को अधिक दंडित किया। जैसा कि स्टडवेल ने उल्लेख किया है, पूर्वोत्तर एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में प्रारंभिक उद्योग संरक्षण पर बल देना निर्यात प्रदर्शन के माध्यम से बाहरी बेंचमार्किंग के साथ-साथ चला। स्थानीय व्यवसायों के लिए विशेष विशेषाधिकार थे, लेकिन निर्यात प्रदर्शन के लिए जवाबदेही थी। इस तरह से पैमाने, उत्पादकता, दक्षता और तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल की गई। स्टडवेल ने इस बात का उल्लेख बार-बार किया है कि कोरियाई औद्योगिक नीति के अंतर्गत निष्पादकों की मदद करने की तुलना में अपने गैर-निष्पादकों को दंडित अधिक किया गया है।

संक्षेप में, औद्योगिक पश्चिम के विकास के अनुभव और पूर्व की चमत्कारिक विकास अर्थव्यवस्थाओं से पता चलता है कि टैरिफ वास्तव में औद्योगीकरण को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख उपकरण था। तथापि, टैरिफ का उपयोग सुविचारित तरीके से किया गया था, और टैरिफ नीतियों को तैयार करने में सरकार के समग्र दृष्टिकोण को अपनाया गया था। अंततः, औद्योगिक नीति के लक्ष्यों को केवल संरक्षण से ही प्राप्त नहीं किया गया, बल्कि उन नीतियों से भी प्राप्त किया गया, जिनसे यह सुनिश्चित हुआ कि संरक्षित उद्योगों ने दिए गए संरक्षण के अनुरूप प्रदर्शन किया।

24 जुहाज, आर., लेन, एन., और रोडिक, डी. (2023)। द न्यू इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्रीयल पॉलिसी”, एनुअल रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स 3, (<https://tinyurl.com/3m5f2t2>).

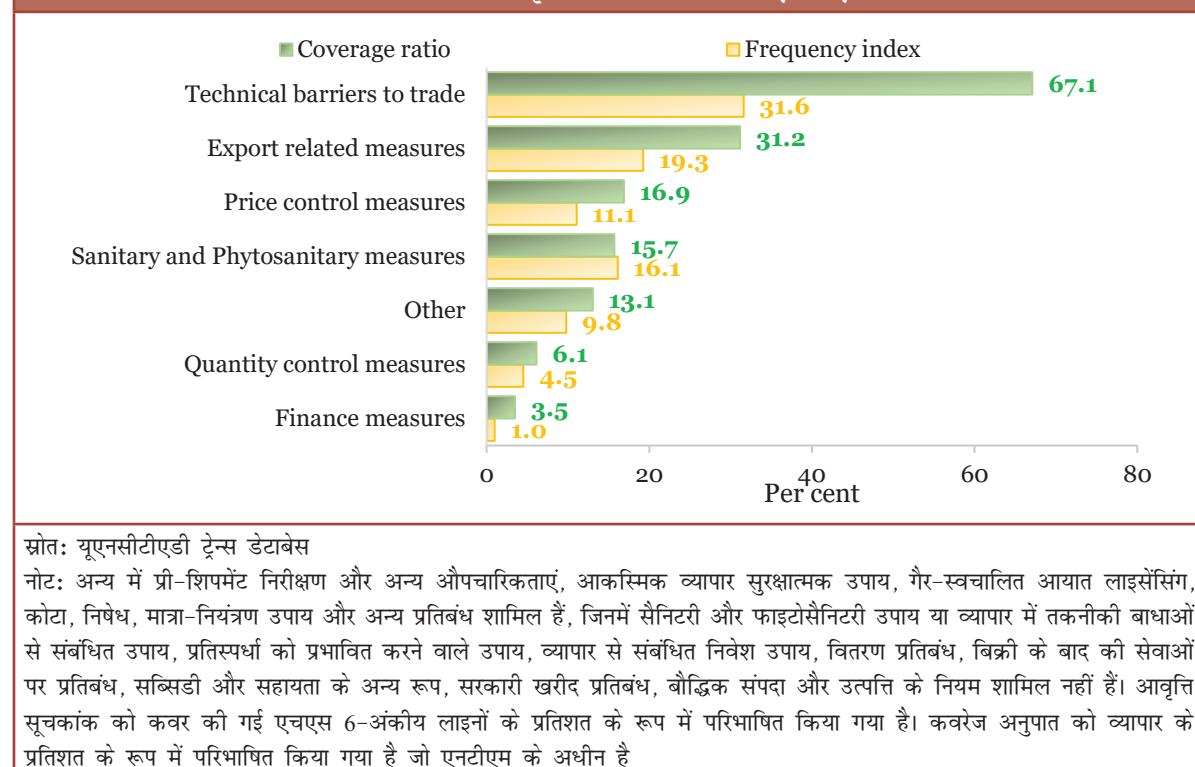
25 उपयुक्त नोट 24.

26 लेन, एन (2022). “मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन्स : इंडस्ट्रीयल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन साउथ कोरिया”, सीएसई वर्किंग पेपर सीरीज, (<https://tinyurl.com/ye2ahh7k>)

गैर-टैरिफ उपाय (एनटीएम)

3.15 जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वैश्विक स्तर पर टैरिफ में गिरावट के साथ-साथ विभिन्न देशों में एनटीएम²⁷ के कार्यान्वयन में भी बृद्धि हुई है। ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटाबेस²⁸ से पता चलता है कि 2020 और 2024 के बीच व्यापार और निवेश से संबंधित 26,000 से अधिक नए प्रतिबंध वैश्विक स्तर पर लगाए गए हैं। इसे अध्याय 5 में और स्पष्ट किया गया है। व्यापार में तकनीकी बाधाएँ (टीबीटी) 31.6 प्रतिशत उत्पाद लाइनों को प्रभावित करती हैं, जिसमें वैश्विक व्यापार का 67.1 प्रतिशत शामिल है (दिसंबर 2024 तक)। इसके बाद 'निर्यात-संबंधी उपाय' आते हैं, जो 19.3 प्रतिशत उत्पाद लाइनों को प्रभावित करते हैं और इसमें वैश्विक व्यापार का 31.2 प्रतिशत शामिल है। एनटीएम से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में कृषि, विनिर्माण और प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं²⁹

चार्ट III.4: कवरेज और आवृत्ति के आधार पर एनटीएम का वर्गीकरण



27 यूएनसीटीएडी एनटीएम को ऐसे नीतिगत उपायों के रूप में परिभाषित करता है जो सामान्य सीमा शुल्क नहीं हैं, लेकिन फिर भी वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ये उपाय या तो व्यापार की मात्रा अथवा कीमतों या दोनों को प्रभावित कर सकते हैं (एनटीएम का वर्गीकरण | यूएनसीटीएडी)। उपर्युक्त वर्गीकरण के आधार पर एनटीएम को आयात-संबंधित और निर्यात-संबंधित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। आयात-संबंधित एनटीएम को आगे "तकनीकी" या "गैर-तकनीकी" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तकनीकी उपायों में सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय (एसपीएस), व्यापार में तकनीकी बाधाएँ (टीबीटी) और लदाई पूर्व (प्री-शिपमेंट) निरीक्षण शामिल हैं। गैर-तकनीकी उपायों में कोटा, सब्सिडी और व्यापार उपायों जैसी पारंपरिक व्यापार नीतियां शामिल हैं, जिनमें अनुचित व्यापार प्रथाओं का समाधान भी शामिल हैं।

वर्ष 2006 में, संयुक्त राष्ट्र ने गैर-टैरिफ बाधाओं (एनटीटी) पर प्रख्यात व्यक्तियों के समूह और मल्टी-एजेंसी सहायता दल (एमएएसटी) की स्थापना की, जिसमें आईएमएफ, ओईसीडी, यूएनसीटीएडी, विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ आदि जैसे आठ अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में, एमएएसटी ने एनटीएम को इकट्ठा करने और उनका मिलान करने के लिए एक कोडिंग प्रणाली बनाई है। एनटीएम के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (संदर्भ: गैर-टैरिफ उपायों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण पर यूएनसीटीएडी रिपोर्ट, <https://tinyurl.com/mr3mp5uk>) का उद्देश्य नए और मौजूदा उपायों पर जानकारी और स्पष्टीकरण प्रदान करना और देशों के बीच उनकी तुलना में सुधार करना था।

28 ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटाबेस, https://www.globaltradealert.org/global_dynamics.

29 यूएनसीटीएडी ट्रेड एनालिसिस एंड इन्फोर्मेशन सिस्टम (टी आर ए आई एन एस) डेटाबेस के आधार पर।

3.16 वैश्विक स्तर पर गैर-टैरिफ उपाय (एनटीएम)जैसे कि सब्सिडी और निर्यात-संबंधी उपायों में राष्ट्रों के औद्योगिक नीतिगत लक्ष्यों की सहायता से वृद्धि हुई हैं³⁰ व्यापक टैरिफ के विपरीत, एनटीएम अपने दृष्टिकोण में सूक्ष्म होते हैं³¹ वे अक्सर कम दिखाई देते हैं, जिससे उनका आकलन करना कठिन हो जाता है।³²

3.17 यूएनसीटीएडी और यूएनईएससीएपी³³ की एक रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमन के लिए देशों द्वारा एनटीएम के बढ़ते उपयोग के साक्ष्य दिखाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि जलवायु परिवर्तन से संबंधित एनटीएम कुल उपायों का केवल 2.6 प्रतिशत है, लेकिन वे कुछ सबसे बड़े और सबसे अधिक CO₂-गहन व्यापार क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव उद्योग, बिजली और ताप जनन, रूपांतरण और भंडारण। परिणामस्वरूप, वैश्विक व्यापार का 26.4 प्रतिशत, जिसका मूल्य 6.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित एनटीएम के अंतर्गत आता है। टीबीटी सभी पहचाने गए जलवायु परिवर्तन-संबंधी एनटीएम का 61 प्रतिशत से अधिक है, इसके बाद निर्यात-संबंधी और मूल्य-नियंत्रण उपाय (दिसंबर 2024 तक) हैं। भविष्य में, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम)³⁴ और यूरोपीय यूनियन डीफोरेस्टेशन मेकेनिस्म (यूरोपीय संघ वन कटाई विनियमन) (ईयूडीआर)³⁵ के रूप में यूरोपीय संघ द्वारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित एनटीएम लागू करने से चीन, भारत और तुर्की जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के निर्यातकों पर व्यापक प्रभाव पड़ने की आशंका है।³⁶ बॉक्स III.2 में सीबीएएम और ईयूडीआर और भारत के निर्यात पर उनके संभावित प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई है।

बॉक्स III.2: सीबीएएम और ईयूडीआर तथा भारत के निर्यात पर उनका संभावित प्रभाव

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र

यूरोपीय संघ द्वारा क्रियान्वित तथा यू.के. द्वारा विचाराधीन, सी.बी.ए.एम. का उद्देश्य आयातित वस्तुओं के लिए कार्बन उत्सर्जन की लागत को घरेलू रूप से उत्पादित उत्पादों के साथ संरेखित करना है। चूंकि ईयू जैसे देश/समूह उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ईटीएस) के तहत अपने उद्योगों को दिए जाने वाले मुफ्त भत्ते को समाप्त कर रहे हैं, इसलिए वे अपेक्षाकृत लचीले पर्यावरणीय नियमों वाले देशों में अपनी खपत को स्थानांतरित होने से रोकने के लिए सी.बी.ए.एम. की शुरुआत कर रहे हैं। इस तंत्र के तहत, आयातक यूरोपीय संघ के कार्बन

30 जुहाज आर, लेन एन, ओडेल्सन ई, पेरेज बीसी. 2023. द हु व, व्हाट, व्हेन, एंड हॉव ऑफ इंडस्ट्रीयल पॉलिसी: ए टेक्स्ट-बेस्ड एप्रोच, <https://tinyurl.com/ytj2rcwp>.

31 उपयुक्त नोट 30.

32 किन्जियस, एल., सेंडकैप, ए., और यालसीन, ई. (2019)। ट्रेड प्रोटेक्शन एंड द रोल ऑफ नॉन-टैरिफ बैरियर्स. रिव्यू ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, 155(4), 603-643 <https://tinyurl.com/dw5pf4w6>.

33 यूएनसीटीएडी एंड यूएनईएससीएपी रिपोर्ट, ट्रेड रेगुलेशंस फोर क्लाइमेट एक्शन: न्यू इनसाइट्स फ्रॉम द ग्लोबल नॉन-टैरिफ मेसर्स डेटाबेस', <https://tinyurl.com/52sfzu93>.

34 सीबीएएम ईयू का एक उपकरण है, जो ईयू में प्रवेश करने वाले कार्बन-गहन वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य निर्धारित करता है, तथा ईयू से इतर देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।

35 ईयूडीआर के तहत ऑपरेटरों और व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ईयू बाजार में रखे गए उत्पाद (i) वनों की कटाई से मुक्त हों (अर्थात्, वे ऐसी भूमि से उत्पन्न न हों जहां 31 दिसंबर 2020 के बाद वनों की कटाई हुई हो); (ii) उनका उत्पादन उस देश के प्रासांगिक कानून के अनुसार किया जाना चाहिए जहां उत्पाद का उत्पादन किया जाता है; और (iii) उत्पादों को ईयू में रखने से पहले उचित परिश्रम विवरण प्रस्तुत करना शामिल है।

36 यूएनसीटीएडी ग्लोबल ट्रेड अपडेट दिसम्बर 2023, 'ग्लोबल ट्रेड एक्सपेक्टेड टू श्रिंक बाई नियरली 5 परसेंट इन 2023 ऐमिड जियोपोलिटिकल स्ट्रेन्स एंड शिपिंग ट्रेड पैटर्न्स', <https://tinyurl.com/5n8ueccb>.

मूल्य निर्धारण नियमों के तहत घरेलू उत्पादकों/निर्माताओं द्वारा भुगतान किए गए कार्बन मूल्य के अनुरूप कार्बन प्रमाणपत्र खरीदेंगे। इस प्रकार, सीबीएएम प्रभावी रूप से कार्बन मूल्य समकरण उपाय है।

ईयू सी.बी.ए.एम. के अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्रों में लोहा और इस्पात, एल्युमीनियम, सीमेंट और उर्वरक शामिल हैं। ईयू सी.बी.ए.एम. के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताएं 1 जनवरी 2024 को शुरू हुई, जिसमें पिछली तिमाही के लिए तिमाही प्रस्तुतियाँ शामिल थीं। हालांकि, यह शुल्क 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। यूके ने अपना स्वयं का सी.बी.ए.एम. भी प्रस्तावित किया है, जो 1 जनवरी 2027 को लागू होने वाला है, जो 'कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र' की ओर एक व्यापक वैश्विक बदलाव को दर्शाता है। यूके सी.बी.ए.एम. के अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्रों में सीमेंट, उर्वरक, कांच, चीनी मिट्टी की चीजें, लोहा और इस्पात, एल्युमीनियम और हाइड्रोजन शामिल हैं। वर्तमान में, यूरोपीय संघ सी.बी.ए.एम. केवल उत्पादन प्रक्रियाओं से होने वाले प्रत्यक्ष उत्सर्जन के संबंध में कार्रवाई करता है, जबकि प्रस्तावित यूके सी.बी.ए.एम. के अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के उत्सर्जन को शामिल करने का इरादा है। सी.बी.ए.एम. का उद्देश्य भौगोलिक क्षेत्रों में कार्बन की कीमतों को समान करना है, जिससे भारत और सबसे कम विकसित देशों जैसे विकासशील सदस्यों के तुलनात्मक लाभ को नकार दिया जाए।

सी.बी.ए.एम. की शुरूआत के लिए दिया गया औचित्य यह है कि यह कार्बन रिसाव को रोकता है।³⁷ कुछ अधिकार क्षेत्र मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर देशों के निर्धारित योगदान का समग्र प्रभाव यदि पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है, तो दुनिया पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर नहीं आएगी। इसलिए, सी.बी.ए.एम. के पीछे तर्क यह है कि जब तक उनके पास समान स्तर के लक्ष्य नहीं होते, तब तक यूरोप में जलवायु परिवर्तन संबंधी नियंत्रण प्रयासों की समग्रता की रक्षा के लिए सी.बी.ए.एम. आवश्यक था, तथा यह सुनिश्चित करना था कि कार्बन रिसाव के कारण वे नष्ट न हो जाएं। इसके अलावा, यूरोपीय संघ से स्टील स्क्रैप निर्यात पर प्रस्तावित प्रतिबंध, जो स्टील उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है, विकासशील देशों की अधिक कार्बन-कुशल स्टील उत्पादन करने की क्षमता में काफी बाधा उत्पन्न करेगा। इस उपाय को इस रूप में देखा जा सकता है कि यूरोपीय संघ दोनों पक्षों के लाभों का आनंद लेने का प्रयास कर रहा है, साथ ही व्यापार प्रतिबंध भी लगा रहा है।

भारत पर संभावित प्रभाव

यूरोपीय संघ को कुल भारतीय निर्यात में सीबीएएम निर्यात की हिस्सेदारी 2014 में 6.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 10.5 प्रतिशत हो गई है।³⁸ तालिका III.1 में यूरोपीय संघ को भारत के निर्यात का वस्तु-वार एक्सपोजर प्रस्तुत किया गया है, जो सीबीएएम से प्रभावित होने की संभावना है।

³⁷ यूरोपियन कमिशन टैक्सेशन एंड कस्टम्स यूनियन वेबसाइट, <https://tinyurl.com/ysbxy866>.

³⁸ 'इंटरमिंगलिंग ऑफ ट्रेड एंड एन्वार्नमेंट पॉलिसी: इम्प्लीकेशंस ऑफ ईयू-सीबीएएम ओन इंडिया एंड LDCs', ईपीडबल्यू, 16 नोवेम्बर 2024 <https://tinyurl.com/yb32jhdp>.

तालिका III.1: सी.बी.ए.एम. निर्यात मूल्य में भारत का एक्सपोजर (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

	2014	2023
लोहा और इस्पात	2962.6	5557.1
एल्युमीनियम	151.4	1801
सीमेंट	4.2	8.3
उर्वरक	0.7	2
स्रोत: यूएन-कॉमट्रेड डेटाबेस (2024)		

विश्व बैंक के रिलेटिव सी.बी.ए.एम. एक्सपोजर इंडेक्स³⁹ के अनुसार, भारत का स्कोर 0.03 है, जो सी.बी.ए.एम. के प्रति उच्च एक्सपोजर को दर्शाता है।⁴⁰ भारत जैसे देशों को आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने और जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन से निपटने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक ऐसा संतुलन बनाना चाहिए जो पर्यावरणीय स्थिरता और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और सबसे कम विकसित देशों की श्रेणी की आर्थिक विकास आवश्यकताओं दोनों का समर्थन करता हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि बहुपक्षवाद वैश्विक व्यापार संबंधों की आधारशिला बना रहे।⁴¹

यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन (ईयूडीआर)

ईयूडीआर (जिसका कार्यान्वयन 2025 के अंत में और छोटे व्यवसायों के लिए 2026 में शुरू होगा) का आशय वनों की कटाई वाली भूमि से प्राप्त उत्पादों की खपत को विनियमित करना है। ईयूडीआर द्वारा विनियमन के अंतर्गत आने वाले प्रासंगिक उत्पादों के संचालकों और व्यापारियों पर कई सख्त नियम लगाए गए हैं।⁴² इसके लिए संचालकों और व्यापारियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि यूरोपीय संघ बाजार में रखे जाने वाले उत्पाद (i) वनों की कटाई से रहित हो (यानी, 31 दिसंबर 2020 के बाद वनों की कटाई वाली भूमि से प्राप्त नहीं होने चाहिए); (ii) उस देश के संगत विधान के अनुसार उत्पादित होने चाहिए जहाँ उत्पाद का उत्पादन किया जाता है; और (iii) यूरोपीय संघ में उत्पादों को रखने से पहले एक विस्तृत ट्रेस और ट्रैक सिस्टम के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला अखंडता सहित एक उचित 'डिलिजेंस स्टेटमेंट' प्रस्तुत करना शामिल है।

विनियमन के अंतर्गत में यूरोपीय संघ द्वारा वन क्षरण और वनों की कटाई के जोखिम को इंगित करने वाली देश-स्तरीय मानकीकरण प्रणाली तैयार करना भी शामिल है। मानकीकरण प्रणाली निम्न, मानक या उच्च जोखिम वाले देशों को वर्गीकृत करने के लिए तीन-स्तरीय प्रणाली पर आधारित होगी, जिसका निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जानकारी और डेटा के आधार पर किया जाएगा कि कोई देश वनों की कटाई को कम करने में सक्रिय है या नहीं। उच्च जोखिम वाले देशों को कम या मानक जोखिम वाले देशों की तुलना में प्रासंगिक उत्पादों के लिए अधिक कर्मठता बरतनी होगी।

39 सीबीएएम एक्सपोजर इंडेक्स को दो मुख्य तत्वों के गणितीय उत्पाद के रूप में मापा जाता है— यूरोपीय संघ को जाने वाले सीबीएएम-संबंधित उत्पाद के किसी देश के निर्यात का हिस्सा और यूरोपीय संघ को निर्यात के प्रति डॉलर सन्निहित कार्बन भुगतान, जो उत्पादन की कार्बन उत्सर्जन तीव्रता और सीबीएएम प्रमाणपत्रों की अनुमानित लागत द्वारा निर्धारित होता है। सीबीएएम एक्सपोजर इंडेक्स को निर्यात के हिस्से को यूरोपीय संघ को निर्यात के प्रति डॉलर सन्निहित कार्बन भुगतान (निर्यातक की उत्सर्जन तीव्रता गुण +100 प्रति टन कार्बन मूल्य) से गुणा करके मापा जाता है।

40 बर्ल्ड बैंक दाता ऑन रिलेटिव सीबीएएम एक्सपोजर इंडेक्स, <https://tinyurl.com/4hbp64z8>.

41 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर।

42 विनियमन में फ्रॉन्टेनरी को प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो वाणिज्यिक गतिविधि के दौरान, प्रासंगिक उत्पादों को बाजार में पेश करता है या उनका निर्यात करता है और फ्वायापारीय को ऑपरेटर के अलावा आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो वाणिज्यिक गतिविधि के दौरान, प्रासंगिक उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराता है।

देशों के इस वर्गीकरण का उपयोग यूरोपीय संघ के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली जाँच का पता लगाने के लिए किया जाएगा। उच्च जोखिम वाले देशों की कम जोखिम वाले देशों की तुलना में अधिक कठोर जाँच की जाएगी।⁴³

विनियमन में सोया, बीफ, पाम आँयल, लकड़ी, कोको, कॉफी, रबर और उनके व्युत्पन्न उत्पाद जैसे चमड़ा, चॉकलेट, टायर या फर्नीचर शामिल हैं।⁴⁴ यह उन ऑपरेटर या व्यापारी पर नियमों के अनुपालन को साबित करने का दायित्व डालता है जो इन उत्पादों को यूरोपीय संघ के बाजारों में बेचना चाहते हैं।⁴⁵ विनियमन के अनुपालन की लागतों में सूचना संबंधी अपेक्षाएं, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम शमन और रिपोर्टिंग दायित्व शामिल हैं। ये लागतें सीमा संबंधी उपाय नहीं हैं, लेकिन किसी देश के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को अन्य देशों की अनुपालन लागतों के मुकाबले प्रभावित करती हैं। इसलिए, यह विनियम विशिष्ट वस्तुओं में यूरोपीय संघ के व्यापारिक भागीदारों के लिए व्यापार लागत (वृद्धि) में परिवर्तन कर देगा।

जी.टी.आर.आई.⁴⁶ अध्ययन के अनुसार, जहां तक भारत के निर्यात का सवाल है, कॉफी, चमड़ा, खाल और चमड़े से बनी वस्तुएं, आयल केक, कागज, पेपरबोर्ड और लकड़ी के फर्नीचर विनियम से अत्यधिक प्रभावित हो सकते हैं। इसके अंतर्गत सीबीएम की तुलना में विनियम के अंतर्गत आने वाली टैरिफ लाइनों की तुलना भी की गई है, जिसमें से सीबीएम में व्यापक उत्पाद शामिल हैं। सीबीएम और ईयूडीआर से ईयू को भारत के 9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात पर असर पड़ने की उम्मीद है, जो दुनिया को भारत के निर्यात का 9 प्रतिशत या ईयू को भारत के निर्यात का 12.9 प्रतिशत है। अध्ययन से पता चलता है कि यह विनियम आयात के विरुद्ध जलवायु के नाम पर अधिक अवरोध खड़ा करके स्थानीय उत्पादन और चयनित कृषि वस्तुओं के निर्यात को प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित करता है।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार, 1990 से 2020 के बीच विश्व स्तर पर वनों की कटाई के कारण लगभग 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए, इस क्षेत्र का आकार यूरोपीय संघ के बराबर है।⁴⁷ यूरोप में, इसी समय अवधि के दौरान वनों की कटाई का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा कृषि भूमि में परिवर्तित होने के कारण हुआ।⁴⁸ वनों की कटाई के बिना यूरोपीय कृषि विकसित नहीं हो सकती थी, और यूरोपीय संघ के वन अधिकार कानून को लागू करने से दोहरे मानदंडों की बू आती है। इस प्रकार, एक ऐसा क्षेत्र जिसने फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण वनों की कटाई का सहारा लिया है, वनों की कटाई वाली भूमि से प्राप्त उत्पादों की खपत को विनियमित करने के लिए यूरोपीय संघ के वन अधिकार कानून को लागू कर रहा है, यह काफी विरोधाभासी प्रतीत होता है, भले ही यह अप्रत्याशित है।

43 31 मई 2023 के विनियमन के अनुसार, "उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत देशों या उनके भागों से संबंधित उत्पादों, संबंधित ऑपरेटरों और व्यापारियों और संबंधित वस्तुओं और संबंधित उत्पादों के उनके हिस्से की मात्रा के संबंध में, एक बड़ा दृष्टिकोण लागू होना चाहिए जो व्यापक कवरेज प्रदान करता है। इस प्रकार सक्षम अधिकारियों को ऑपरेटरों और व्यापारियों के एक निश्चित प्रतिशत की जाँच करने की आवश्यकता होनी चाहिए, जबकि प्रासंगिक उत्पादों के एक विशिष्ट प्रतिशत को भी कवर करना चाहिए। कम या मानक जोखिम के रूप में वर्गीकृत देशों या उनके भागों से संबंधित उत्पादों के संबंध में, सक्षम अधिकारियों को ऑपरेटरों और व्यापारियों के कम से कम एक निश्चित प्रतिशत की जाँच करने की आवश्यकता होनी चाहिए। उच्च जोखिम वाले देशों या उनके भागों से संबंधित उत्पादों के लिए जाँच का स्तर अधिक होना चाहिए जबकि यह मानक या कम जोखिम वाले देशों या उनके भागों के लिए कम हो सकता है।"

44 विनियमन के अंतर्गत शामिल उत्पादों की सूची 31 मई 2023 के विनियमन के अनुलग्नक-I में उपलब्ध है, जो <https://tinyurl.com/bddmuysp> पर उपलब्ध है।

45 विनियमन के अनुच्छेद 2 (15) में कहा गया है, "एक ऑपरेटर एक प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति है जो वाणिज्यिक गतिविधि के दौरान प्रासंगिक उत्पादों को संघ के बाजार में पेश करता है या उन्हें संघ के बाजार से निर्यात करता है।"

46 दिनांक 1 अगस्त 2023 का जीटीआरआई ब्रीफ, 'डिफोरेस्टेशन एंड कंप्लायांस चौलेंज़: ए ब्लो टू इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट्स एज ईयू डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन (ईयूडीआर) डेडलाइन लूप्स', <https://gtri.co.in/gtriFlagshipRep12.pdf>.

47 यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एप्रीकल्चर ओर्गनाइजेशन, <https://tinyurl.com/3fzhythxj>.

48 <https://tinyurl.com/44mu2hnj>.

संक्षेप में, इस निष्कर्ष से छुटकारा पाना कठिन है कि सी.बी.ए.एम. और ई.यू.डी.आर. दोनों ही जलवायु और पर्यावरण की भाषा में लिपटे व्यापार संरक्षण उपाय हैं। खेल और अंतिम लक्ष्य एक ही हैं, लेकिन रणनीतियाँ बदलती रहती हैं। श्रम मानक, लिंग, लोकतंत्र, उत्सर्जन और वनों की कटाई... समय के साथ नई सूची बनती रहेगी। विकास के साथ संस्थाएँ और पद्धतियाँ विकसित होती हैं। आज के विकसित देश उन मानकों के अनुरूप नहीं हैं, जिनकी वे विकासशील देशों से अपेक्षा करते हैं, जो विकास के समान चरण में हैं। लेकिन फिर, बौद्धिक स्थिरता वास्तव में यहाँ लक्ष्य नहीं है।

3.18 टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार/विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत लगातार समझौतों के माध्यम से दुनिया भर में टैरिफ के उपयोग में गिरावट के कारण और खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण के बारे में बढ़ती उपभोक्ता चिंताओं के कारण एनटीएम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ती भूमिका निभा रहे हैं।⁴⁹ यूएनसीटीएडी⁵⁰ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एनटीएम वैध नीतिगत साधनों के रूप में काम कर सकते हैं, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। कुछ मामलों में, वे व्यापार को भी बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई निर्यातक देश उच्च स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी मानकों को लागू करता है, तो आयात करने वाले देशों के उपभोक्ताओं को खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता पर अधिक भरोसा होता है, जिससे मांग में वृद्धि हो सकती है। सख्त घरेलू खाद्य सुरक्षा मानक स्थानीय निर्यातकों को अपने व्यापार भागीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद कर सकते हैं, जिससे व्यापार के अवसरों को और बढ़ावा मिलेगा।

3.19 हालांकि कई एनटीएम का मुख्य उद्देश्य लोक स्वास्थ्य या पर्यावरण की रक्षा करना है, लेकिन वे सूचना, अनुपालन और प्रक्रियात्मक लागतों को बढ़ाकर व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालते हैं। यह निर्यातकों और आयातकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाजारों तक पहुँचना और उनसे लाभ उठाना तेजी से व्यापार विनियमों, जैसे कि स्वच्छता मानकों और उत्पाद गुणवत्ता आवश्यकताओं के पालन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, खाद्य उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों को सीमित करने वाले विनियम का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पोषण की रक्षा के एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त करना है। हालांकि, यह विनियम निर्यातक देशों में फर्मों पर अतिरिक्त अनुपालन अपेक्षाएं लगाता है, और कुछ को लग सकता है कि निर्यात करना अब लाभदायक नहीं है। नतीजतन, ऐसे विनियम व्यापार को प्रतिबंधित कर सकते हैं, जिससे निर्यातक देशों में आय कम हो सकती है और आयातक देशों में उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं। यह मुद्दा मुख्य रूप से छोटे निर्यातकों और गरीब देशों को प्रभावित करता है, क्योंकि इन्हें अक्सर इन एनटीएम से असंगत नुकसान उठाते हैं।⁵¹

3.20 एनटीएम आयात पर अपने प्रभाव के माध्यम से एफडीआई को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यदि इस दृष्टिकोण से जुड़ी लागत निर्यात की लागत से कम है, तो कोई फर्म एफडीआई में शामिल होकर एनटीएम के वैकल्पिक मार्ग का निर्णय ले सकती है। इसके अतिरिक्त, एनटीएम उन्हें लागू करने वाले देश में आवक एफडीआई को प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय बाजार पहुँच में बाधाएं बढ़ाते हैं। अनुसंधानों से पता चला है की एनटीएम का एफडीआई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी उत्पाद पर लागू एनटीएम की औसत संख्या में एक की वृद्धि होती है, यानी प्रति उत्पाद 2.5 से 3.5 एनटीएम, तो एफडीआई में 12 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। कुछ एनटीएम, जैसे बौद्धिक

49 यूएनसीटीएडी डॉक्यूमेंट, 'नॉन-टैरिफ मेसर्स: डेफिनिशंस एंड बेसिक फैक्ट्स', <https://tinyurl.com/y7hwd55u>

50 यूएनसीटीएडी रिपोर्ट, 'ट्रेड कॉस्ट्स ऑफ नॉन-टैरिफ मेजर्स नॉव मोर देन डबल देत ऑफ टैरिफ्स', <https://tinyurl.com/55tk5fut>.

51 यूएनसीटीएडी डॉक्यूमेंट ओन 'इंट्रोडक्शन टू एनटीएम', <https://tinyurl.com/mr3a95en>

संपदा अधिकार, स्थानीय सामग्री आवश्यकताएं और विशिष्ट क्षेत्रों में टीबीटी, एफडीआई को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।⁵²

भारत के व्यापार प्रदर्शन में रुझान

3.21 भारत के व्यापार क्षेत्र ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उल्लेखनीय स्थिरता और वृद्धि का प्रदर्शन किया है। वैश्विक मंदी और महामारी के बीच वित्त वर्ष 20 में गिरावट के बाद, वित्त वर्ष 22 में कुल निर्यात में जोरदार उछाल आया और वित्त वर्ष 23 में रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुंच गया। यह गति वित्त वर्ष 24 में भी जारी रही, जिसमें कुल निर्यात पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को पार कर गया, जबकि जबरदस्त घरेलू मांग के जवाब में आयात में थोड़ी कमी आई।

3.22 भारत के कुल निर्यात (माल + सेवाएँ) ने वित्त वर्ष 25 के पहले नौ महीनों में सकारात्मक गति दिखाई है, जो 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें साल-दर-साल 6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि निर्यात के लचीलेपन को प्रदर्शित करती है, जो वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हाल के वर्षों में लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान कुल आयात 682.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें साल-दर-साल 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह सकारात्मक आयात वृद्धि भारतीय बाजार में वस्तुओं की स्थिर मांग का संकेत देती है, जो घरेलू खपत और उत्पादन जरूरतों को सहयोग प्रदान करती है। निर्यात की तुलना में समग्र आयात में अधिक उल्लेखनीय वृद्धि के कारण अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान समग्र व्यापार घाटा 69.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 25 की इसी अवधि में 79.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

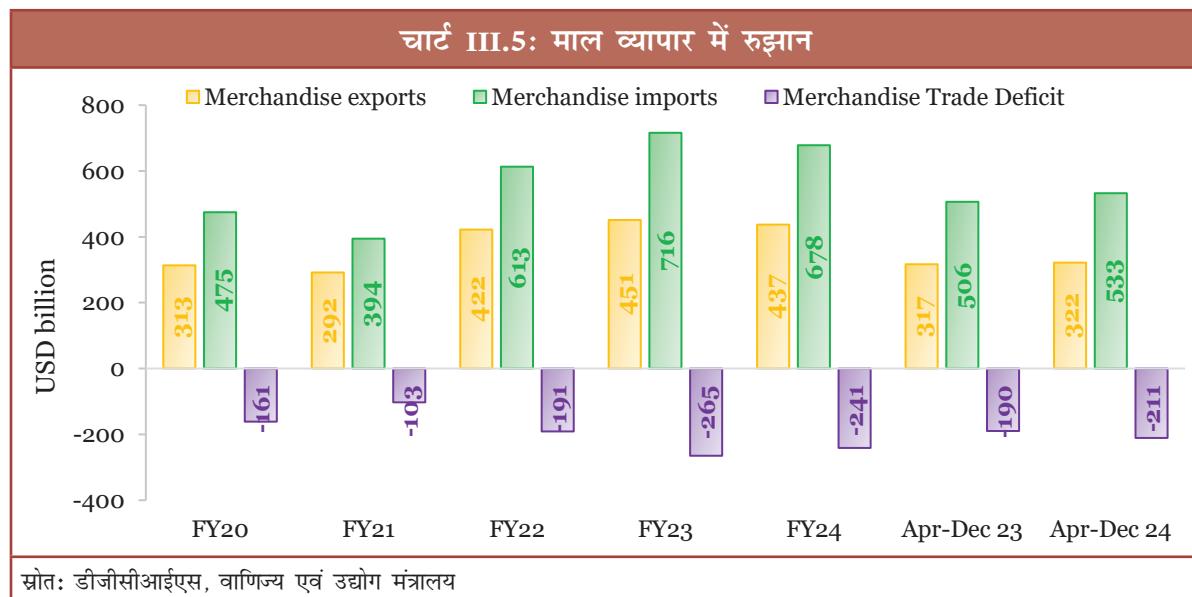
3.23 अप्रैल-दिसंबर 2024 में गैर-पेट्रोलियम निर्यात में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी समय में, गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न और आभूषण निर्यात में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरी सामान और रसायनों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में निर्यात में वृद्धि देखी गई जो अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान साल-दर-साल आधार पर क्रमशः 6.4 प्रतिशत, 28.6 प्रतिशत, 9.9 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की वृद्धि वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान कपड़ा निर्यात⁵³ में भी सालाना आधार पर 7.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अनाज, दालों और खाद्य तेलों पर बढ़ते मुद्रास्फीति के दबाव ने कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात को सीमित कर दिया। कुल मिलाकर, व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में 1.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष आधार) की वृद्धि दर्ज की गई है जिसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय वस्तु कीमतों में गिरावट के कारण पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात मूल्य में कमी रही।

3.24 अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान व्यापारिक आयात में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से गैर-तेल, गैर-सोने के आयात में वृद्धि के कारण हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 340.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 25 के पहले आठ महीनों में 352.1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई, जो मुद्रास्फीति के प्रभाव के बावजूद घरेलू खपत में उछाल का संकेत है। त्यौहारी खर्च से पहले फ्रांटलोडिंग और सुरक्षित-संपत्तियों की मांग के कारण उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों के कारण सोने के आयात में वृद्धि हुई। प्रमुख गैर-तेल, गैर-सोने के आयातों में, अलौह धातु, मशीन टूल्स,

⁵² उपयुक्त नोट 50.

⁵³ कपड़ा निर्यात में सूती धागा/कपड़े/मेड-अप', हथकरघा उत्पाद, मानव निर्मित धागा/कपड़े/मेड-अप, सभी 'विभिन्न फाइबर-आधारित सामग्रियों' के रेडीमेड परिधान, फर्श कवरिंग, कालीन और हस्तनिर्मित कालीन को छोड़कर हस्तशिल्प सहित जूट निर्माण शामिल हैं।

मशीनरी, इलेक्ट्रिकल और गैर-इलेक्ट्रिकल सामान और परिवहन उपकरण ने वित्त वर्ष 25 के पहले नौ महीनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जो पूँजीगत माल की बढ़ती मांग को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान ने भी लगातार गति बनाए रखी, जो विवेकाधीन उपभोक्ता खर्च में वृद्धि का संकेत है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादन का समर्थन करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए दालों और कपास के आयात में वृद्धि हुई।



3.25 निर्यात की तुलना में माल के आयात में वृद्धि की तेज गति ने अप्रैल-दिसंबर 2024 में व्यापारिक वस्तु व्यापार घाटे को 210.8 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने में योगदान दिया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 189.7 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

कपड़ा निर्यात

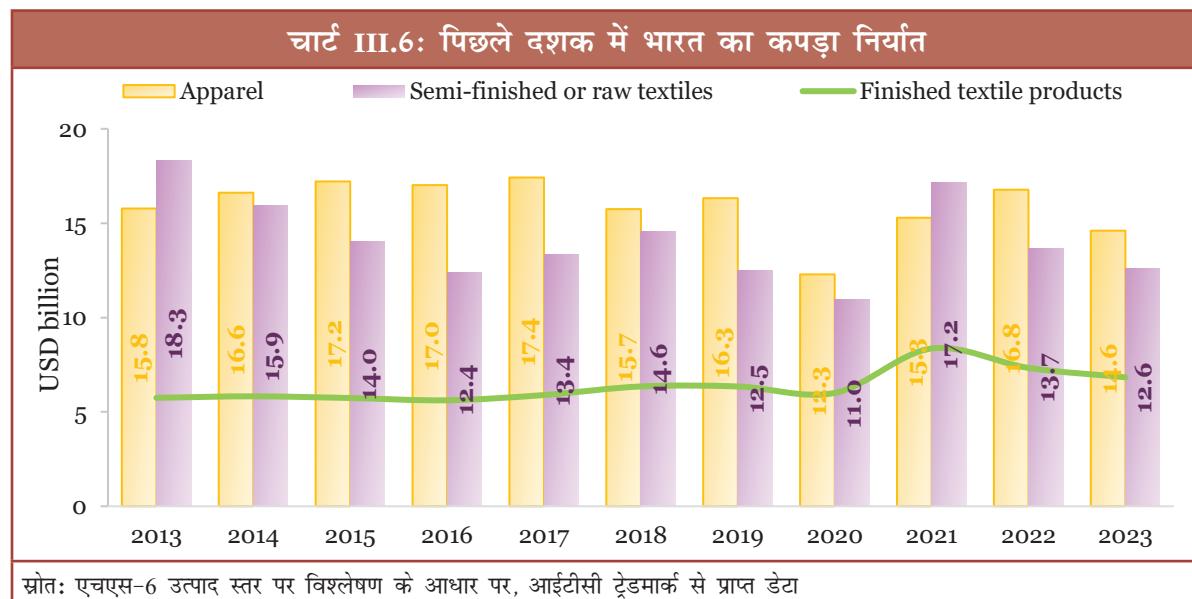
3.26 भारत का कपड़ा क्षेत्र सदियों से राष्ट्र के लिए गौरव और शक्ति का विषय रहा है। अनूठे प्रिंट और बुनाई से लेकर विविध रंगों और हस्तकला तक, कपड़ा क्षेत्र हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विरासत के विभिन्न पहलुओं को बुनता है। भारत वैश्वक स्तर पर कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। कपड़ा और परिधान उद्योग सकल घरेलू उत्पाद में 2.3 प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में 13 प्रतिशत और निर्यात में 12 प्रतिशत का योगदान देता है।⁵⁴ यह कृषि के बाद सबसे बड़े रोजगार सृजनकर्ताओं में से एक है, जिसमें 45 मिलियन से अधिक लोग सीधे रोजगार पाते हैं, जिनमें कई महिलाएँ और ग्रामीण आबादी शामिल हैं।⁵⁵ इस उद्योग की समावेशी प्रकृति के एक और सबूत के रूप में, इसकी लगभग 80 प्रतिशत क्षमता देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई समूहों (क्लस्टरों) में फैली हुई है।⁵⁶

⁵⁴ <https://www.ibef.org/industry/textiles>

⁵⁵ उपयुक्त नोट 54.

⁵⁶ इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट, 'टेक्सटाइल - अपारेल इंडस्ट्री: द चेंज एंजेंट ऑफ इंडिया', <https://tinyurl.com/mtzhfarh>.

3.27 भारत ने 2023 में 34 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की कपड़ा वस्तुओं का निर्यात किया, जिसमें परिधान निर्यात बास्केट का 42 प्रतिशत (14.6 बिलियन अमरीकी डॉलर) था, उसके बाद कच्चे माल/अर्ध-तैयार सामग्री 34 प्रतिशत (11.7 बिलियन अमरीकी डॉलर) और तैयार गैर-परिधान सामान 30 प्रतिशत (7.8 बिलियन अमरीकी डॉलर) थे।⁵⁷ यूरोप और अमेरिका ने भारत के परिधान निर्यात का लगभग 66 प्रतिशत, तैयार गैर-परिधान सामान का 58 प्रतिशत और कच्चे माल/अर्ध-तैयार सामग्री का 12 प्रतिशत उपभोग किया। अन्य प्रमुख गंतव्यों में यूके (परिधान निर्यात का 8 प्रतिशत) और यूएई (7 प्रतिशत) शामिल हैं।



3.28 आम तौर पर, भारतीय कपड़ा निर्यात बास्केट का रुझान कपास और कपास आधारित उत्पादों की ओर रहा है। उदाहरण के लिए, 2023 में, शीर्ष 10 कपड़ा निर्यातों (मूल्य के हिसाब से) में से आठ में कपास और कपास आधारित उत्पाद शामिल थे। भारत की प्रमुख कपड़ा निर्यात श्रेणी, यानी परिधान के संबंध में, देश की बाजार हिस्सेदारी 2023 में वैश्विक स्तर पर 2.8 प्रतिशत रही। हालांकि, यह उद्योग के प्रमुख खिलाड़ियों, जैसे चीन (30 प्रतिशत), बांग्लादेश (9 प्रतिशत) और वियतनाम (7 प्रतिशत) की तुलना में बहुत कम है। एच एस-6 स्तरों पर आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत लगभग 3 बिलियन अमरीकी डॉलर के परिधान निर्यात के लिए अन्य निर्यातकों⁵⁸ को कड़ी प्रतिस्पर्धा देता है, लेकिन वस्तुओं का शेष परिधान संग्रह अभी भी हमारे प्रतिस्पर्धियों के तुलनात्मक लाभ से मेल नहीं खाता है।

3.29 वर्ष 2020 से 2022 के बीच कोविड-19 की अवधि के दौरान कपड़ा निर्यात लचीला रहा, लेकिन एक दशक की समयावधि में उनका प्रदर्शन कमज़ोर रहा है। बॉक्स III.3 में निर्यात वृद्धि में बाधा डालने वाले संभावित कारकों और उन अवसरों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिनका उपयोग इस क्षेत्र को 2030 तक कपड़ा निर्यात में 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करना होगा।⁵⁹

57 टैरिफ स्तर पर संयुक्त राष्ट्र कॉमट्रेड डेटा पर आधारित विश्लेषण।

58 एचएस-6 स्तर पर निर्यात का बाजार हिस्सा चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के बाजार हिस्से के बराबर या उससे अधिक है।

59 दिनांक 4 सितंबर 2024 के वस्त्र मंत्रालय की पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति, <https://tinyurl.com/5he5722d>.

बॉक्स III.3: अब समय आ गया है कि हम अपने ताने-बाने के बारे में सजग हो जाएं!

लागतें जो कपड़े के नियात में वृद्धि को कम कर रही हैं

भारत का कपड़ा उत्पादन देश भर में फैले कई स्वतंत्र और समूहबद्ध लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) में होता है। उदाहरण के लिए, कपास उत्पादन को लें, जो गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। कपास की ताजा उपज फिर तमिलनाडु जाती है, जहां कपास के धागे का उत्पादन होता है। फिर सूती कपड़े में बुने जाने से पहले धागे महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में जाते हैं। स्थानीयकरण की कमी और मूल्य श्रृंखला की जटिलता के कारण, वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में लागत अधिक होती है। इसके विपरीत, चीन और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों में उर्ध्वाधर एकीकृत 'फाइबर-टू-फैशन' फर्म कम लागत वाले उत्पाद नियात करती हैं, निरंतर गुणवत्ता बनाए रखती हैं और उद्योग की तेजी से बदलती प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम हैं।

सरल और उदार सीमा शुल्क प्रक्रियाएं विनियामक लागत को और कम कर देती हैं और चीन और वियतनाम जैसे वैश्विक कपड़ा प्रतिस्पर्धियों के नियात को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करती हैं।

दूसरी ओर, भारत में कपड़ा नियातक जटिल प्रक्रियाओं से विवश हैं, उदाहरण के लिए, नियातकों को प्रयुक्त कपड़े, बटन और जिपर के प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर का सावधानीपूर्वक हिसाब रखना पड़ता है। इसी तरह, कपड़ा आयात के लिए प्री-शिपमेंट निरीक्षण प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है, जिससे प्रचालन गति धीमी हो जाती है और कपड़ा व्यवसाय की लागत बढ़ जाती है।⁶⁰

संरचनात्मक विशेषताओं (जैसे ऊर्ध्वाधर एकीकरण, उदार श्रम कानून, आदि) के अलावा, जो लागत लाभ प्रदान करते हैं, कपड़ा बाजार में प्रतिस्पर्धियों को उपभोक्ता देशों के साथ एफटीए का अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। वास्तव में, भारतीय परिधान नियात को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में समान अवसर का सामना नहीं करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जैसा कि मुखर्जी एवं अन्य. 2019⁶¹ द्वारा उल्लेख किया गया है, भले ही भारत को रेशम शॉल और स्कार्फ के नियात में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ है, लेकिन देश को अमेरिका में 11.3 प्रतिशत की उच्च टैरिफ दर का सामना करना पड़ता है। इसकी तुलना में, कोरिया जैसे प्रतिस्पर्धियों को यूएस-कोरिया एफटीए जैसे व्यापार करारों के कारण अपने रेशम स्कार्फ नियात पर शून्य टैरिफ का सामना करना पड़ता है।

सामान्य तौर पर, आने वाले वर्षों में कपड़ा उद्योग की लागत में वृद्धि होने की संभावना है। संधारणीय सोर्सिंग की ओर वैश्विक संरचनात्मक बदलाव इसे आगे बढ़ाएगा। अक्सर, नियामक परिवर्तनों के कारण ऐसा बदलाव आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के पास 16 विधियाँ हैं जिसमें संपूर्ण फैशन मूल्य श्रृंखला शामिल होती है, जो 2021 और 2024⁶² के बीच लागू हुए। चूंकि यूरोपीय संघ हमारे नियात का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा है, इसलिए इस तरह का बदलाव छोटे उद्यमों के लिए एक चुनौती है, जिन्हें पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय-अनुकूल उत्पादन विधियों को अपनाने की आवश्यकता है।

वैश्विक कपड़ा उद्योग में बदलते रुझान

भारत के पास परिधान की मांग में उभरते वैश्विक बदलावों के साथ तालमेल बिठाने का एक शानदार अवसर है। जबकि हमारा तुलनात्मक लाभ कपास और कपास आधारित उत्पादों में निहित है, वैश्विक मांग मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) से बने उत्पादों की ओर स्थानांतरित हो गई है। एमएमएफ-आधारित उत्पादों में योग पैट और एथलेटिक वियर से लेकर विमानन, एयरोस्पेस और ऑटोमोबाइल में तकनीकी वस्त्र शामिल हैं।

60 जीटीआरआई रिपोर्ट, जुलाई 2024, 'हॉव कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, इंपोर्ट रिस्ट्रक्शन्स एंड डोमेस्टिक इंटरेस्ट्स हिंडर इंडियाज गारमेंट एक्सपोटर्स' <https://tinyurl.com/yxjxjzyz>.

61 आइडियाज फोर इंडिया, 'ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड दिएर इमैक्ट ओन इंडियाज अपारेल एक्सपोटर्स', <https://tinyurl.com/22exauh4>.

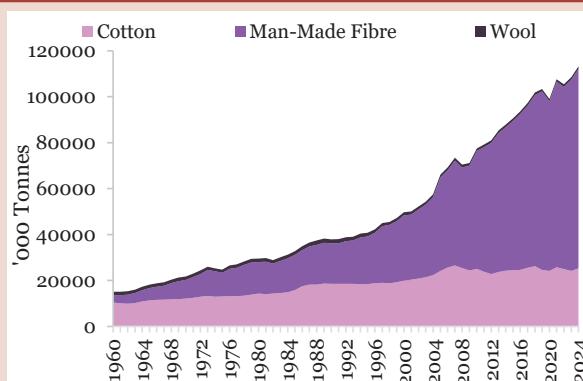
62 मैकिन्से आर्टिकल, 'रिइमेजिनिंग द अपारेल वैल्यू चैन अमिड वोलेटिलिटी', <https://tinyurl.com/2nhedse4>.

इंटरनेशनल कॉटन एसोसिएशन के अनुसार, 2024 में वैश्विक फाइबर खपत में एमएमएफ का हिस्सा 77 प्रतिशत था, जबकि कपास के लिए यह सिर्फ 22 प्रतिशत था।

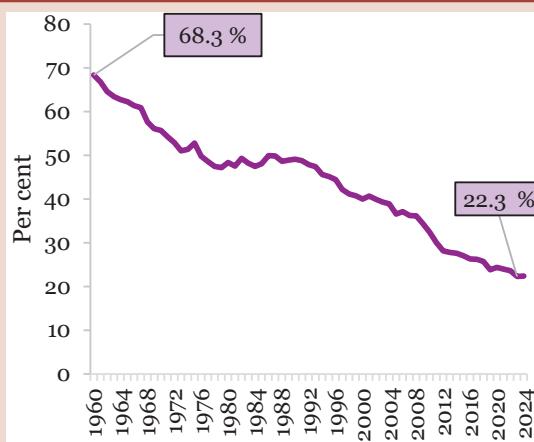
एमएमएफ मूल्य श्रृंखला में शामिल होकर, भारत वैश्विक एमएमएफ मांग में लगातार वृद्धि से लाभान्वित होगा। वैश्विक एमएमएफ उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में 9.2 प्रतिशत है, और वियतनाम, चीन और ताइवान जैसे वैश्विक नेताओं के उत्पादन स्तरों को पकड़ने की क्षमता अधिक है।⁶³

हमारी प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता से मेल खाने और एमएमएफ उत्पादन से मूल्य लाभ प्राप्त करने के लिए, हमारे एमएमएफ क्षेत्र को ऊर्ध्वाधर एकीकरण की ओर बढ़ना चाहिए और अनुसंधान और विकास और टिकाऊ उत्पादन तकनीकों में महत्वपूर्ण रूप से निवेश करना चाहिए।

चार्ट III.7: प्रमुख कपड़ा फाइबरों (रेशों) की विश्व खपत



चार्ट III.8: फाइबर के लिए वैश्विक बाजार में कपास की बाजार हिस्सेदारी



स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय कपास संघ (आईसीए)

भारत के कपड़ा निर्यात को वैश्विक खरीदारों के लिए तैयार करना - हाल की योजनाएँ और आगे के अवसर

हाल के वर्षों में, सरकार ने वैश्विक मांग की बदलती प्रकृति और भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली उच्च सापेक्ष लागतों के जवाब में कई नीतियों की घोषणा की है। इस क्षेत्र के लिए ₹10,683 करोड़ के परिव्यय के साथ एक पीएलआई योजना लागू की गई है, जो उद्योग में निवेश के माध्यम से क्षमता निर्माण को बढ़ाती है। चूंकि एमएमएफ उत्पादों को विभिन्न उपयोग मामलों के अनुकूल भारी शोध और विकास की आवश्यकता होती है, इसलिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) को ₹1,480 करोड़ के परिव्यय की मंजूरी दी गई है। 2024 तक, एनटीटीएम मिशन के तहत 168 शोध परियोजनाओं (₹509 करोड़ मूल्य की) को मंजूरी दी गई थी।⁶⁴

एक ऊर्ध्वाधर एकीकृत कपड़ा उद्योग की आवश्यकता के जवाब में, सरकार ने विश्व स्तरीय प्लग-एंड-प्लग बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और कपड़ा क्षेत्र में एफडीआई को आमंत्रित करने के लिए 2022 में सात स्थलों पर प्रधानमंत्री मेंगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम-मित्र) पार्कों को मंजूरी दी है।

63 वर्ल्ड टेक्सटाइल डिमांड रिपोर्ट, 2024 के अनुसार; <https://tinyurl.com/52m82u5>.

64 वस्त्र मंत्रालय की प्रेस सूचना ब्यूरो की 12 नवंबर 2024 की विज्ञप्ति, <https://tinyurl.com/4kf8sdnz>.

विश्व स्तरीय, मानकीकृत अवसंरचना कपड़ा निर्यातकों को उद्योग में बदलती ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) आवश्यकताओं का बेहतर ढंग से जवाब देने में भी मदद करेगा। लागत प्रतिस्पर्धा में मदद करने के लिए, सरकार ने अंतरिम केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 25 में परिधान/वस्त्र और मेड-अप के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों (आरओएससीटीएल) की छूट के लिए योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी।⁶⁵ इसके अलावा, यूएई-भारत सीईपीए (2022) जैसे गहरे एफटीए ने एक महत्वपूर्ण बाजार के साथ भारत के कपड़ा टैरिफ को कम करने में मदद की है। भारत यूरोपीय संघ और यूके जैसे शीर्ष आयातकों के साथ व्यापार सौदों पर बातचीत करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

भारत के कपड़ा क्षेत्र में कई अनुकूल परिस्थितियां काम कर रही हैं। उदाहरण के लिए, मैकिन्से के मुख्य खरीद अधिकारी सर्वेक्षण के अनुसार, दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी (मात्रा प्रतिबद्धताओं सहित) बनाने की तलाश करने वाले खरीद अधिकारियों की हिस्सेदारी 2019 और 2023 के बीच दोगुनी से अधिक हो गई है।⁶⁶ इसके अलावा, सर्वेक्षण में शामिल 40 प्रतिशत से अधिक खरीद अधिकारियों ने भारत, बांग्लादेश और वियतनाम से अपने स्रोत को बढ़ाने की योजना बनाई है।

हालांकि कुछ ऐसे अनुकूल परिस्थितियां हैं जो भारत के कपड़ा निर्यात की वृद्धि का समर्थन करेंगी, लेकिन कपड़ा बास्केट की लागत कम किए बिना और एमएमएफ क्षेत्र में हमारे बाजार हिस्से को गहरा किए बिना इनका पूरी तरह से दोहन नहीं किया जा सकता है। इन उद्देश्यों के लिए उद्योग को अपने शोध प्रयासों को बढ़ाने और उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और संधारणीयता संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एकीकृत और तैयार करने की आवश्यकता होगी।

हमारे निर्यातकों की वित्तीय और प्रबंधकीय बैंडविडथ का उपभोग करने वाली प्रक्रियाओं का सरलीकरण, समेकन और उन्मूलन एक आसान काम है। इन चुनौतियों का समाधान करने से लागत में उल्लेखनीय कमी आ सकती है और निर्यातकों पर बोझ कम हो सकता है, जिससे उन्हें अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी।

नए बाजारों में भारत के निर्यात का विविधीकरण

3.30 जैसा कि समय के साथ आर्थिक कार्य विभाग⁶⁷ के निबंध-संग्रह में चर्चा की गई है, भारत ने अपनी निर्यात बास्केट में बड़ी संख्या में नए उत्पादों को जोड़ा है। 1994 और 2022 के बीच, भारत ने न केवल नए बाजारों को उकेरा है, बल्कि कुछ नई उत्पाद श्रेणियों में बाजार के लीडर बन गए हैं। उदाहरण के लिए, भारत शिपिंग जहाजों (लगभग 33 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ) का शीर्ष निर्यातक है। इसी तरह, यह लोहे और स्टील मिश्र धातुओं का एक प्रमुख निर्यातक है, जो 1994 से पहले एक अस्पष्टीकृत बाजार है।

3.31 अप्रैल और नवंबर 2024 के बीच, भारत के निर्यात ने उच्च वैश्विक चुनौतियों के बावजूद विविध बाजारों में महत्वपूर्ण वृद्धि और विस्तार देखा। विश्लेषण में विविध बाजारों की संख्या को दर्शाया गया है, जिसमें बिल्कुल नए बाजार शामिल हैं, जहां अप्रैल और नवंबर 2023 के बीच कोई निर्यात नहीं देखा गया था, लेकिन निर्यात वित्त वर्ष 25 की संबंधित अवधि में हुआ। इसमें नए बाजार भी शामिल हैं जहां निर्यात शेयर अप्रैल से नवंबर 2023 तक 0-0.1 प्रतिशत था और वित्त वर्ष 25 की संबंधित अवधि में 25 प्रतिशत से अधिक मूल्य में वृद्धि के साथ 0.1 प्रतिशत से अधिक हो गया। इसके अलावा, होनहार बाजार, जहां अप्रैल से नवंबर 2023 में निर्यात शेयर 0.1-1 प्रतिशत था और अप्रैल से नवंबर 2024 में 25 प्रतिशत से अधिक मूल्य में वृद्धि के साथ 1 प्रतिशत से अधिक हो गया। डॉट का आकार निर्यात के मूल्य को दर्शाता है। विश्लेषण प्रमुख वस्तुओं (पीसी) के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

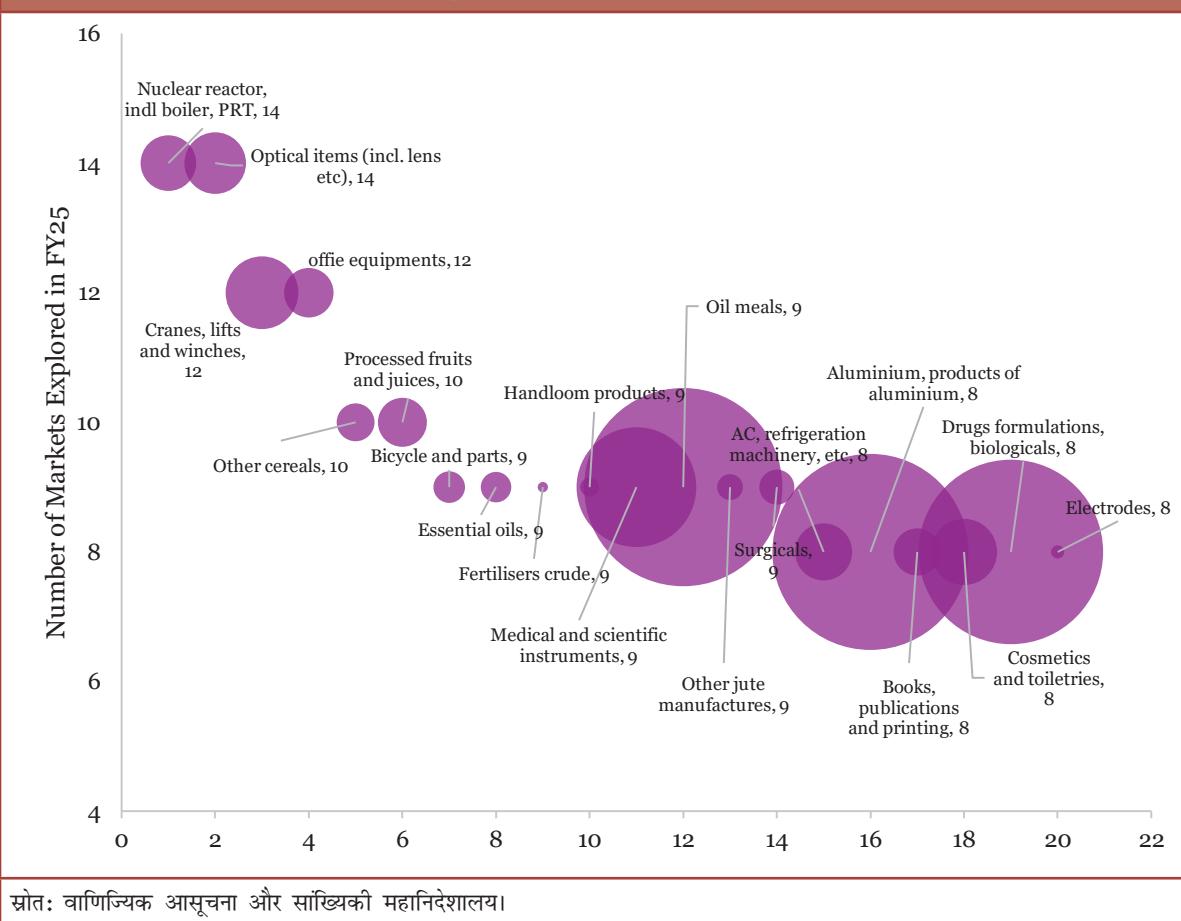
65 पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 1 फरवरी 2024, <https://tinyurl.com/35faj878A>

66 मैकिन्से आर्टिकल, 'रिमेजिनिंग द अपारेल वैल्यू चैन अमिड बोलेटिली', <https://tinyurl.com/2nhedse4>.

67 फिर से जांच करने वाले कथाओं: निबंधों का एक संग्रह, <https://tinyurl.com/4rap2xpx>

3.32 इन 20 पीसी को दो मानदंडों के आधार पर चुना गया था: सबसे पहले, पीसी को नए बाजारों की संख्या के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया गया था, और दूसरी बात, पीसीएस का निर्यात मूल्य 100 मिलियन से अधिक का निर्यात मूल्य था। उदाहरण के लिए, चार्ट III-15 से पता चलता है कि ऑप्टिकल आइटम का निर्यात मूल्य अप्रैल से नवंबर 2024 तक 16.6 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात मूल्य था और उन्हें 14 नए बाजारों (जिम्बाब्वे, वियतनाम, तंजानिया, युगांडा, घूनीशिया, रोमानिया, कतर, फिलीपींस, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, कुवैत, दक्षिण कोरिया, इराक, घाना, फिनलैंड) को निर्यात किया गया था। इसी तरह, क्रेन, लिफ्टों और विजेता के निर्यात का अप्रैल से नवंबर 2024 तक 23.1 मिलियन अमरीकी डालर का मूल्य था, जिसे 12 नए बाजारों (ताइवान, सोमालिया, पुर्तगाल, म्यांमार, मोरक्को, मैडागास्कर, लिथुआनिया, जॉर्जिया, हांडुरास, कैमरून, आर्मेनिया) को निर्यात किया गया है। इसके अलावा, कार्यालय उपकरण और चिकित्सा-वैज्ञानिक उपकरणों में क्रमशः यूएसडी 10.7 मिलियन (12 नए बाजारों में निर्यात) और यूएसडी 62.7 मिलियन (9 नए बाजारों में निर्यात) का निर्यात मूल्य है। सर्जिकल को 5.4 मिलियन अमरीकी डालर के कुल मूल्य के साथ नौ नए बाजारों में भी निर्यात किया गया है।

**चार्ट III.9: महत्वपूर्ण पीसी के लिए खोजे गए नए बाजारों की संख्या
(अप्रैल - नवंबर 2024)**

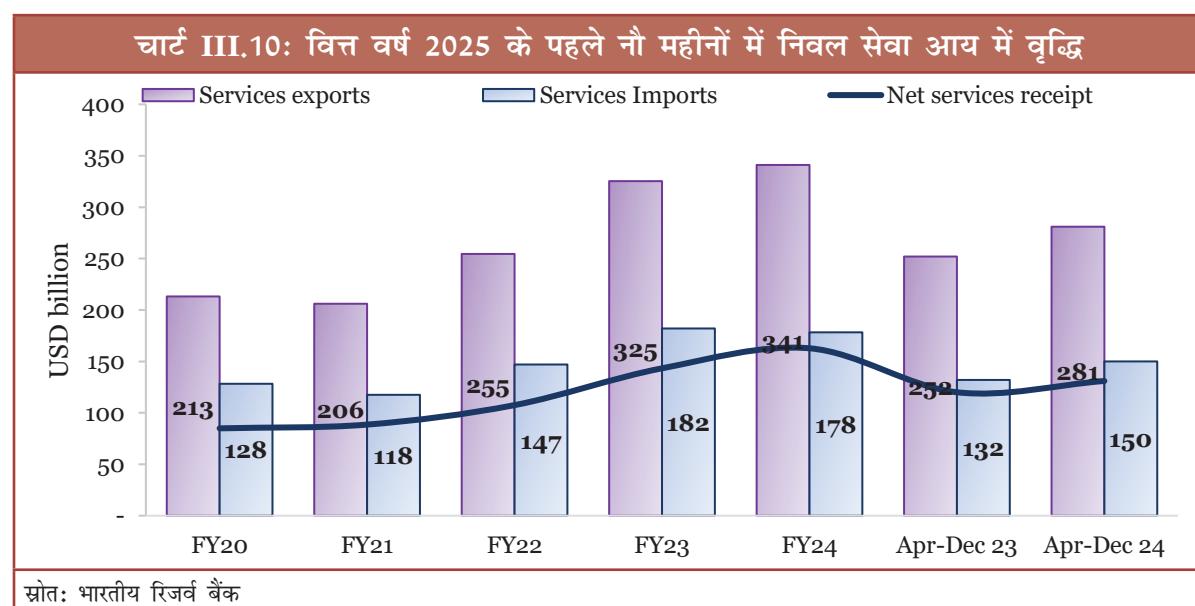


3.33 ये रुझान भारत की क्षमता को बनाए रखने और यहां तक कि स्थापित बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की क्षमता को दर्शाते हैं। यह वैश्विक परिदृश्यों को विकसित करने में देश की लचीलापन और अनुकूलनशीलता को भी उजागर करता है। इसके साथ ही, नए बाजारों की खोज ने अपने निर्यात

पहुंच का विस्तार करने और किसी भी एकल बाजार या क्षेत्र पर निर्भरता को कम करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत दिया। यह विविधीकरण रणनीति बाजार में उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को कम करती है और देश के आर्थिक विकास में योगदान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य में भारत को एक अधिक प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है।

वैश्विक चुनौतियों के बीच सेवा व्यापार लचीला रहा

3.34 सेवा क्षेत्र के निर्यात ने लचीलापन का प्रदर्शन किया है, जबकि माल के निर्यात में हाल के महीनों में संयम देखा गया है। प्रतिकूल भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच वित्त वर्ष 25 के पहले नौ महीनों में वे 11.6 प्रतिशत की दर से बढ़े। सेवाओं के निर्यात में वृद्धि ने वित्त वर्ष 25 के पहले नौ महीनों में वित्त वर्ष 2014 के पहले नौ महीनों में 120.1 बिलियन अमरीकी डालर से लेकर 131.3 बिलियन डॉलर की राशि में वृद्धि में योगदान दिया।



3.35 भारत से सेवा निर्यात ने वैश्विक निर्यात में बहु-क्षेत्रीय उपस्थिति दिखाई है, जिसमें कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान रहा है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी से भी अधिक हो गई है, जो 2005 में 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में लगभग 4.3 प्रतिशत हो गई है।⁶⁸ ‘दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं’ में, भारत की हिस्सेदारी वैश्विक निर्यात बाजार की 10.2 प्रतिशत है (विश्व में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है), जो आईटी आउटसोर्सिंग, सॉफ्टवेयर विकास और डिजिटल सेवाओं में अपनी मजबूत स्थिति को दर्शाता है। ‘अन्य व्यावसायिक सेवा क्षेत्र’ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें विश्व में भारत की हिस्सेदारी 7.2 प्रतिशत है (दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है), जो वृत्तिक और परामर्शी सेवाओं में अपनी विशेषज्ञता से प्रेरित है।⁶⁹

3.36 ‘यात्रा’ और ‘परिवहन’ सेवाएं उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जहां भारत वैश्विक निर्यात में अपेक्षाकृत कम हिस्सा रखता है, क्रमशः 2.1 प्रतिशत और 2.2 प्रतिशत, दुनिया भर में अन्य पर्यटन और लाजिस्टिक्स हब से प्रतिस्पर्धा का सामना करने की संभावना है। आगे की वृद्धि के अवसर हैं, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बुनियादी ढांचे और वैश्विक परिवहन नेटवर्क को बढ़ाने में। वैश्विक बैंकिंग, बीमा और

68 UNCTAD Stats, <https://tinyurl.com/2s42av87>.

69 यूएनसीटीएडी-डब्ल्यूटीओ आंकड़ों पर आधारित।

निवेश सेवाओं में वृद्धि की क्षमता को उजागर करते हुए, भारत का वित्तीय सेवा क्षेत्र वैश्विक औसत से पीछे है। दूसरी ओर, व्यक्तिगत, 'सांस्कृतिक और मनोरंजन' सेवाओं में 3.4 प्रतिशत और 'निर्माण सेवाओं' में 3.5 प्रतिशत की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ, भारत क्रमशः 6वें और 8वें स्थान पर है, जो सांस्कृतिक निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को प्रदर्शित करता है।

3.37 भारत आईटी और व्यावसायिक सेवाओं में वैश्विक लीडर बना हुआ है, लेकिन यात्रा, परिवहन और वित्तीय सेवाओं में पर्याप्त संभावना है जिनका प्रयोग नहीं किया गया है। चूंकि देश 'वैश्विक क्षमता केंद्रों' का केंद्र बन रहा है और नवप्रवर्तन जारी है, कौशल विकास और रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करना इस गति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। उभरते क्षेत्रों को मजबूत करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना यह सुनिश्चित करेगा कि भारत आने वाले समय में सेवा क्षेत्र में एक प्रमुख प्रतिभागी बना रहे।

ई-कॉर्मस निर्यात

3.38 भारत में ई-कॉर्मस उद्योग में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विस्तार हुआ है, जो ऑनलाइन भुगतान, स्थानीयकृत वितरण सेवाओं, ग्राहकों के साथ डेटा-संचालित आदान प्रदान और डिजिटल मार्केटिंग जैसे प्रौद्योगिकी-संचालित उन्नतिकरण में वृद्धि जैसे विभिन्न तत्वों से प्रेरित है। एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक व्यवसाय-से-उपभोक्ता (बी 2 सी) ई-कॉर्मस बाजार 2022 में 5.7 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2026 तक 8.1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक 9.1 प्रतिशत के सीएजीआर पर बढ़ने की उम्मीद है। इसके विपरीत, भारत का बी 2 सी ई-कॉर्मस बाजार 2022 में 83 बिलियन अमरीकी डालर का मूल्य था, और यह 2026 तक 150 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ने का अनुमान है, जो 15.9 प्रतिशत का सीएजीआर दिखाता है⁷⁰ हालांकि, वर्तमान बाजार के आकार से, भारत का ई-कॉर्मस बाजार एक छोटा सा अंश बनाता है, जो वैश्विक बाजार का लगभग 1.5 प्रतिशत है, और यह आने वाले वर्षों में लगभग 2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इन निर्यातों ने वित्त वर्ष 23 के दौरान अनुमानित यूएसडी 4 से 5 बिलियन का उत्पादन किया और वर्ष 2030 तक यूएसडी 200 से बढ़कर 300 बिलियन यूएसडी तक बढ़ने की उम्मीद है।⁷¹ बॉक्स III-4 उन कारकों और नीतियों पर चर्चा की गई है जिन्होंने भारत के ई-कॉर्मस निर्यात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बॉक्स III.4: भारत के ई-कॉर्मस निर्यात को बढ़ावा देने वाले कारक

डेटा कनेक्टिविटी का विस्तार, स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच, डिजिटल वॉलेट की उपलब्धता और उपयोग में वृद्धि और सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान, ग्राहकों के बढ़ते हुए आय स्तर और डिजिटल शॉपिंग प्लेटफॉर्म के प्रति बढ़ती अभिज्ञता ने भारत के ई-कॉर्मस निर्यात को बढ़ावा दिया है। ग्राहक कुशल कारीगरों से ज्यादा से ज्यादा कस्टमाइज्ड उत्पाद प्रसंद करते हैं और भारत इस मांग को पूरा करने के लिए हस्तनिर्मित वस्तुओं की अपनी समृद्ध परंपरा का लाभ उठा सकता है। इसके अतिरिक्त, निर्यातक एजेंटों और दुकानदारों जैसे बिचौलियों से जुड़ी लागतों को कम करके अपना लाभ बढ़ा सकते हैं, जिससे ई-कॉर्मस उत्पादों को बेचने का एक आकर्षक विकल्प बन रहा है।⁷²

70 एसोचैम और ईवाई की रिपोर्ट, 'इनेबलिंग ई-कॉर्मस एक्सपोटर्स फ्रॉम इंडिया', <https://tinyurl.com/ye29x47m>.

71 प्रेस सूचना ब्यूरो, बाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की दिनांक 31 मार्च 2023 की प्रेस विज्ञप्ति, <https://tinyurl.com/ny9psh8e>.

72 मार्च 2023 की जीटीआरआई रिपोर्ट, 'मेकिंग ई-कॉर्मस एक्सपोटर्स ए बिगर सक्सेस स्टोरी देन आई टी: ए ब्लूप्रिंट फोर रियलाइजिंग ईंडियाज ई-कॉर्मस एक्सपोटर्स पोटेशियल', <https://gtri.co.in/gtriRep8-pdf>.

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी सरकारी पहलों ने एमएसएमई और ई-कॉर्मस निर्यात के प्रति समर्थन और ध्यान बढ़ाया है, जिससे अधिक घरेलू विक्रेताओं के वैश्वक होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इन पहलों ने व्यवसायों को फलने-फूलने और अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया है। ई-कॉर्मस निर्यात की प्रासंगिकता को स्वीकार करते हुए, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 ने सीमा पार डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने और ई-कॉर्मस और अन्य उभरते निर्यात चौनलों को बढ़ावा देने के प्रावधान किए हैं। इनमें निर्यात बंधु योजना⁷³, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) योजना के तहत ई-कॉर्मस निर्यातकों को वित्तीय सहायता, निर्यात और पैकिंग ऋण⁷⁴, ई-कॉर्मस निर्यात हब⁷⁵, डाक निर्यात केंद्र⁷⁶ और इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र (ई-बीआरसी)⁷⁷ शामिल हैं। इसके अलावा, जीएसटी व्यवस्था शून्य-रेटेड आपूर्ति⁷⁸ का लाभ प्रदान करती है।⁷⁹

हाल ही में, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉर्मस बाजार के प्रतिभागियों के सहयोग से राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं। इनमें ई-निर्यात हाट⁸⁰ का आयोजन और ई-कॉर्मस निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी ई-कॉर्मस प्रतिभागियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना आदि शामिल हैं।⁸¹ उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में डिजाइन, प्रौद्योगिकी और बाजार पहुंच का लाभ उठाकर पैकेजिंग और निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के उपायों को कार्यान्वित किया है। सरकार छोटे उत्पादकों को एग्रीगेटर्स को बेचने की सुविधा के लिए ई-कॉर्मस हब स्थापित करने की भी योजना बना रही है।⁸² तेलंगाना सरकार ने एक नई एमएसएमई नीति की घोषणा की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉर्मस पोर्टल (ओएनडीसी पोर्टल) और सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल (जीईएम पोर्टल) पर विक्रेताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करके एमएसएमई में ई-कॉर्मस की पैठ बढ़ाने पर विचार किया गया है।⁸³

केंद्र सरकार की ई-कॉर्मस एक्सपोर्ट हब (ई सीईएच) पहल का उद्देश्य भारत के सीमा पार ई-कॉर्मस में क्रांति लाना है। ये हब एसएमई, कारीगरों और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) उत्पादकों को वैश्वक बाजारों से जोड़ते हैं, जिससे टियर 2 और टियर 3 शहरों में लॉजिस्टिक्स दक्षता और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा मिलता है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर, संशोधित मूल्य निर्धारण स्लैब

73 देश से ई-कॉर्मस निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायता एवं आउटरीच कार्यक्रम, क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रम।

74 नकदी प्रवाह में सुधार और विनिर्माण लागत में सहायता के लिए पूर्व और पश्चात शिपमेंट दोनों चरणों के लिए संपादित कम व्याज वित्तपोषण की पेशकश, <https://tinyurl.com/5cfwwxtx>.

75 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से, इसका उद्देश्य सीमा पार ई-कॉर्मस गतिविधियों के लिए सुविधाओं (भंडारण, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रमाणन, परीक्षण आदि) और बुनियादी ढांचे को केंद्रीकृत करना है।

76 डाक मार्ग के माध्यम से ई-कॉर्मस निर्यात को बढ़ावा देने की योजना, डाक मार्ग के माध्यम से ई-कॉर्मस निर्यात को बढ़ाने के लिए विदेशी डाकघरों के सहयोग से हब और स्पोक मॉडल के रूप में काम करेगी।

77 उन्नत इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण (ई-बीआरसी) प्रणाली का पायलट आधार, जिसके तहत निर्यातक अपने ई-बीआरसी को स्वयं प्रमाणित कर सकते हैं।

78 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(47) के अनुसार, किसी आपूर्ति को छूट प्राप्त तब कहा जाता है, जब उस पर शुल्क की दर शून्य हो या उसे अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई हो या कर के दायरे से बाहर रखा गया हो (अर्थात्, गैर-जीएसटी आपूर्ति)।

79 इससे निर्यातक को ऐसी आपूर्तियों पर चुकाए गए कर की वापसी और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलयूटी) के तहत अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की वापसी का दावा करने में सहायता मिलती है।

80 अमेजन न्यूज, 'डब्ल्यूबीआईसीएस, अमेजन एंड फिक्की जोइन हैंडिस टीओ प्रोपोर्ट ई-कॉर्मस एक्सपोर्ट्स फॉर लेक्स ऑफ एमएसएमई इन द स्टेट', <https://tinyurl.com/5AFKC7Zs>.

81 अमेजन न्यूज, 'अमेजन साइन एन एम आ यू विद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक टू ड्राइव ई-कॉर्मस एक्सपोर्ट्स फॉर लेक्स ऑफ एमएसएमई इन द स्टेट', <https://tinyurl.com/5AFKC7Zs>.

82 इंडियन ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स न्यूज, 'फिलपक्ट ओपन्स न्यू फुलफिलमेंट सेंटर्स इन उन्नाव, वाराणसी', <https://tinyurl.com/37zs4h4v>.

83 तेलंगाना का निर्यात रणनीति ढांचा मसौदा, <https://tinyurl.com/ysf69a8z>.

अब ₹10 करोड़ से अधिक के ऑर्डर के लिए ₹3 लाख तक सीमित है, जिससे लेनदेन की लागत में काफी कमी आई है। दुबई में भारत मार्ट भारतीय एमएसएमई को खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी), अफ्रीकी और सीआईएस बाजारों तक सस्ती पहुंच प्रदान करता है, जिससे इन क्षेत्रों में निर्यात बढ़ता है।⁸⁴

भारत में ई-कॉर्मर्स निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र विनियामक ढांचे और अनुपालन दायित्वों से संबंधित कुछ चुनौतियों के साथ-साथ विकास के अवसर प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, विक्रेताओं और ई-कॉर्मर्स प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों की भूमिकाओं को अभी तक स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसके लिए निर्यात और भुगतान प्रक्रियाओं के विभिन्न चरणों में विक्रेताओं और ई-कॉर्मर्स ऑपरेटरों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। वर्तमान में, निर्यात को दो प्राथमिक मोड़, कूरियर और कार्गो के माध्यम से सुविधा दी जाती है, जिसमें 12,000 अमरीकी डालर (₹10 लाख) की कूरियर निर्यात मूल्य सीमा होती है, जो अन्य देशों की तुलना में कम है।⁸⁵ इसके अतिरिक्त, पारंपरिक और ई-कॉर्मर्स निर्यात के लिए अलग-अलग सीमा शुल्क पर्यवेक्षण कोडों की अनुपस्थिति के कारण सीमा शुल्क सत्यापन में देरी होती है, जिससे भविष्य में नीतिगत हस्तक्षेप के लिए डेटा संग्रहण में बाधा उत्पन्न होती है।⁸⁶

आरबीआई 1999 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का प्रबंधन करता है, जिसे शिपमेंट के नौ महीने के भीतर विदेशी मुद्रा प्राप्तियों की आवश्यकता होती है। यह समयरेखा कुशल लेनदेन का समर्थन करती है, लेकिन ई-कॉर्मर्स ऑपरेटरों के लिए 12 से 18 महीनों में बेचे जाने वाले शिपमेंट को संभालने वाली चुनौतियों का सामना कर सकती है। यह अधिक लचीले सामंजस्य की समयसीमा की खोज करने के लिए द्वार खोलता है। निर्यात डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (ईडीपीएमएस) भुगतान सामंजस्य में सहायक है जिसकी रेंज यूएसडी 18 से यूएसडी 36 (₹1,500-₹3,000) तक की लागत है। इसके लिए यह लागत अनुकूलन, विशेष रूप से छोटे-मूल्य शिपमेंट के लिए, की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, ई-कॉर्मर्स रिफंड/रिजेक्ट के पुनः आयात को शुल्क से तभी छूट दी जाती है जब यह साबित हो जाए कि पुनः आयातित माल निर्यात किए गए माल के समान ही है, जो एक बोझिल प्रक्रिया है। इन्हें और अधिक सरल बनाने से परिचालन दक्षता में सुधार हो सकता है।⁸⁷⁹¹

भारत के ई-कॉर्मर्स निर्यात में काफी वृद्धि हुई है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन गया है। मौजूदा चुनौतियों में से कुछ को समाधान करने से इस क्षेत्र के लिए अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने और प्रमुख वैश्विक ई-कॉर्मर्स निर्यातकों के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अवसरों को अनलॉक किया जा सकता है।

निर्यातकों के लिए व्यवसायिक पहल करने की सुगमता

3.39 भारत की विनिर्माण और निर्यात क्षमताओं को मजबूत करने के लिए लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लॉजिस्टिक्स हब का विकास, बुनियादी ढांचे में निवेश और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार के लिए नीतिगत सुधार इस दिशा में उपाय हैं। ऐसे प्रयासों का उद्देश्य भारतीय व्यवसायों के लिए लागत कम करना, निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माल की तेज, सुगम आवाजाही को सक्षम बनाना है। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

3.40 कागज रहित ई-बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र (ई-बीआरसी) प्रणाली से 2.5 मिलियन ई-बीआरसी के लिए सालाना लागत में ₹125 करोड़ से अधिक की कमी आई है, इससे प्रक्रियाएं कारगर हुई हैं और

84 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2079986>.

85 चीन के मामले में, ई-कॉर्मर्स निर्यात के लिए खेप की सीमा USD 50,000, https://content.dgft.gov.in/Website/EcommExportHandBokMSME_E.pdf.

86 उपयुक्त नोट 70.

87 उपयुक्त नोट 70.

इसने निर्यातकों को एफटीपी के तहत योजनाओं से लाभान्वित होने में मदद की है। इसने प्रशासनिक और पर्यावरणीय दोनों खर्चों में कटौती की है। छोटे निर्यातकों, विशेष रूप से ई-कॉर्मस में, उच्च-मात्रा, कम-लागत वाले लेनदेन को संभालने में प्रणाली की दक्षता से लाभान्वित हुए हैं, जिससे वे अधिक प्रभावी ढंग से लाभ और रिफंड का दावा करने में सक्षम हुए हैं।

3.41 विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) का एक नया "ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म" लॉन्च किया गया है, जो निर्यातकों को नए बाजारों को जोड़ने में सक्षम बनाने वाली एकल खिड़की पहल है। ई-प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य को बदलना है। एमएसएमई मंत्रालय, एकिजम बैंक, वित्तीय सेवा विभाग और विदेश मंत्रालय सहित प्रमुख भागीदारों के सहयोग से विकसित यह प्लेटफॉर्म निर्यातकों को व्यापक समर्थन और संसाधन प्रदान करके सूचना विषमता को दूर करने के लिए तैयार है। यह प्लेटफॉर्म वन-स्टॉप समाधान है, जो निर्यातकों को महत्वपूर्ण व्यापार-संबंधी सूचनाओं तक लगभग वास्तविक समय तक पहुंच प्रदान करता है, जबकि उन्हें प्रमुख सरकारी संस्थाओं जैसे कि विदेश में भारतीय मिशन, वाणिज्य विभाग, निर्यात संवर्धन परिषद यह ई-प्लेटफॉर्म 6 लाख से अधिक आईईसी (आयातकर्ता निर्यातक कोड) धारकों, 180 से अधिक भारतीय मिशन अधिकारियों और 600 से अधिक निर्यात संवर्धन परिषद अधिकारियों के अलावा विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग (डीओसी), बैंकों आदि के अधिकारियों को जोड़ेगा।

3.42 डीजीएफटी व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप विदेश व्यापार नीति अपडेट, आयात/निर्यात नीति, निर्यात/आयात सांख्यिकी, आवेदनों की स्थिति और 24x7 वर्चुअल सहायता के बारे में सभी जानकारी प्रदान करता है। विभाग ई-आईईसी का 24x7 ऑटो-जनरेशन भी प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ताओं को आईईसी के लिए किसी भी अनुमोदन की प्रतीक्षा न करने में सक्षम बनाता है। आईईसी विवरण स्वचालित रूप से सीबीडीटी, एमसीए और पीएफएमएस सिस्टम पर स्वतः प्रमाणित हो जाते हैं।

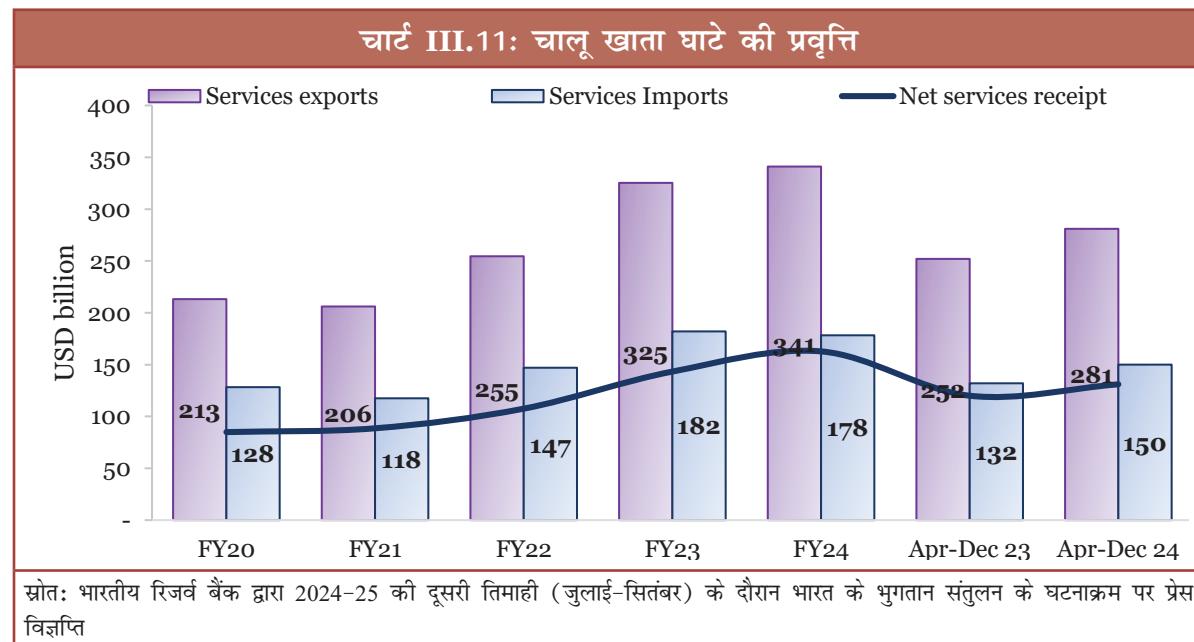
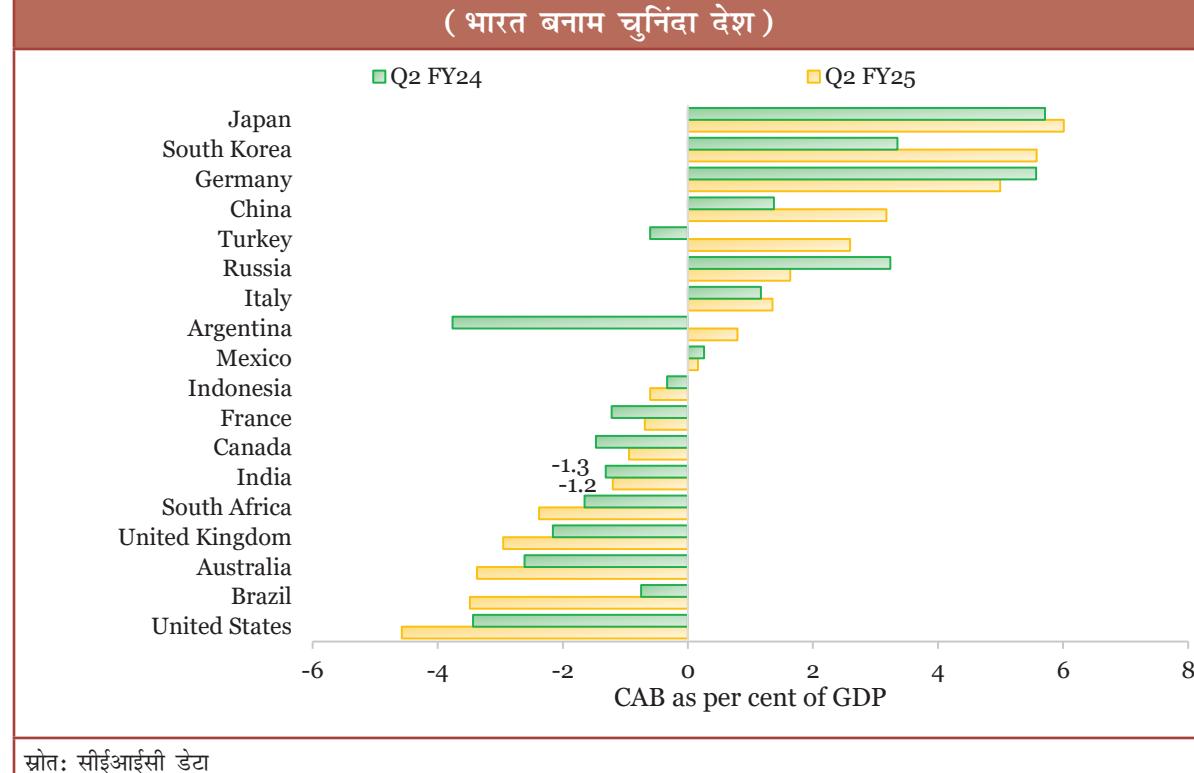
भुगतान संतुलन: चुनौतियों के बीच सुदृढ़

3.43 विदेशी व्यापार और निवेश के माहौल में अनिश्चितताओं की पृष्ठभूमि में, भारत की भुगतान संतुलन (बीओपी) स्थिति स्थिर बनी हुई है, जिसका कारण सेवाओं के निर्यात में लचीलापन, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, विदेशी पोर्टफोलियो में नए सिरे से निवेश और (एफडीआई) प्रवाह में सुधार है। इस खंड में इन प्रवृत्तियों पर चर्चा की गई है।

चालू खाता

3.44 भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में जीडीपी के 1.2 प्रतिशत पर थोड़ा कम हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में यह जीडीपी के 1.3 प्रतिशत पर दर्ज किया गया था। सीएडी में हालिया वृद्धि का श्रेय वस्तु व्यापार घाटे में वृद्धि को दिया जा सकता है, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 64.5 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 75.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। बढ़ती निवल सेवा आय और निजी धन-अंतरण आय में वृद्धि ने व्यापारिक व्यापार घाटे में विस्तार को कम किया। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में निवल सेवा प्राप्तियां बढ़कर 44.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जो वित्त वर्ष 2024 की इसी तिमाही में 39.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

चार्ट III.11: चालू खाता घाटे की प्रवृत्ति

चार्ट III.12: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष
(भारत बनाम चुनिंदा देश)

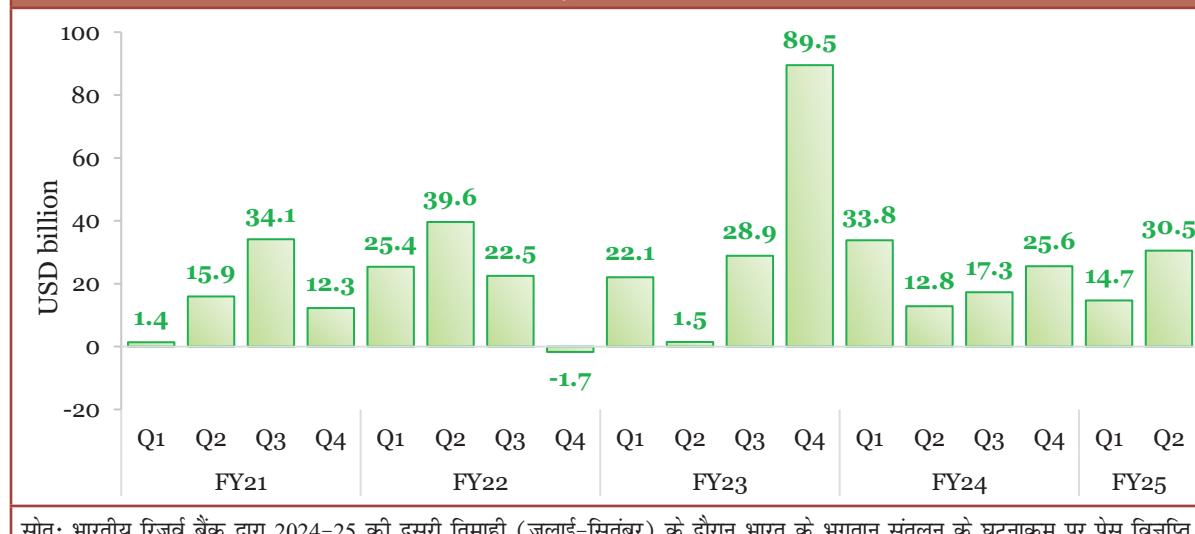
3.45 भारत का चालू खाता घाटा अन्य जी-20 अर्थव्यवस्थाओं, जैसे ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, की तुलना में अपेक्षाकृत नियंत्रित रहा है, जिन्हें उच्च वस्तु मूल्यों और कमज़ोर वैश्विक मांग सहित समान बाह्य दबावों का सामना करना पड़ा है।

3.46 निजी अंतरण भुगतान, मुख्य रूप से विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा धन-प्रेषण द्वारा संचालित, निवल धन अंतरण का बड़ा हिस्सा बना, जो वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में 28.1 बिलियन अमरीकी डॉलर से लगातार बढ़कर वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में 31.9 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। यह वृद्धि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के प्रवासी समुदाय की निरंतर मजबूती और मजबूत प्रेषण अन्तर्वाह को दर्शाती है।

पूंजी और वित्तीय खाता

3.47 पूंजी और वित्तीय खाता भुगतान संतुलन का एक महत्वपूर्ण खंड है, जो चालू खाता घाटे के वित्तपोषण और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए प्राथमिक तंत्र के रूप में कार्य करता है। वित्त वर्ष 23 की पहली तिमाही से वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही तक की अवधि में, भारत ने आम तौर पर पूंजी खाते में अधिशेष दर्ज किया है, जो मुख्य रूप से एफडीआई, एफपीआई और विदेशी ऋणों से मजबूत अन्तर्वाह द्वारा संचालित है। इन प्रवाहों ने देश की वैदेशिक स्थिति को मजबूत किया है और विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में योगदान दिया है।

चार्ट III.13: निवल पूंजी अंतर्वाह में तिमाही रुझान

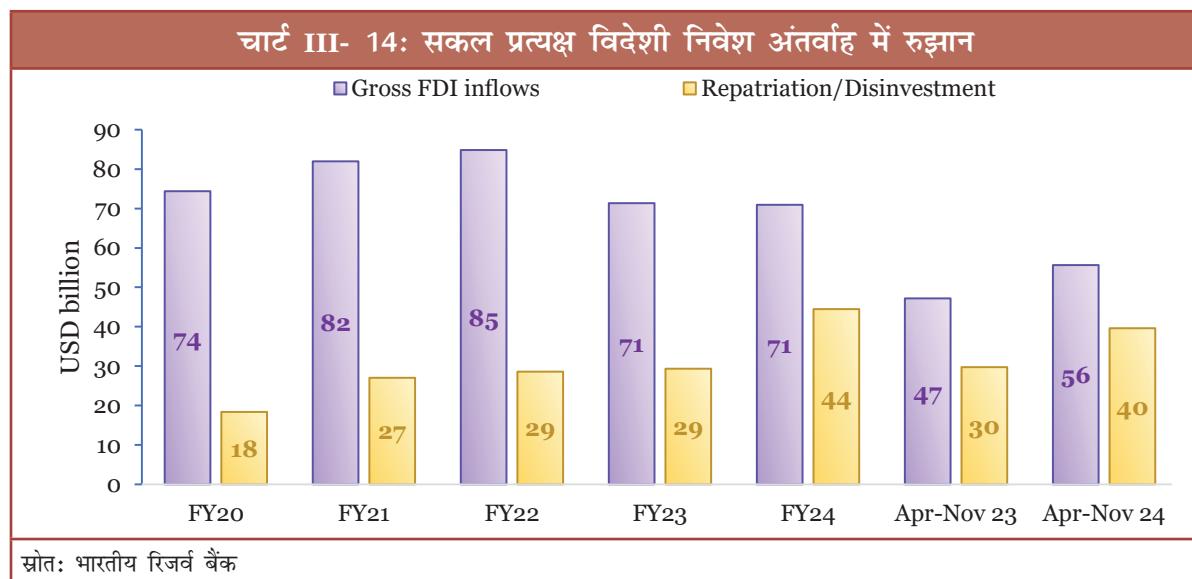


3.48 पूंजी अंतर्वाह का वृद्धि प्रक्षेपक्र के हाल की तिमाहियों में पुनरुद्धार के संकेत दिखाए हैं। वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में, निवल पूंजी अंतर्वाह (इनफ्लो) 30.5 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज किए गए 12.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से उल्लेखनीय वृद्धि है। इस वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से एफपीआई अंतर्वाह, विदेशी वाणिज्यिक उधार और एनआरआई जमा में वृद्धि को दिया जा सकता है।

एफडीआई प्रवाह का कार्य निष्पादन

3.49 एफडीआई ने वित्त वर्ष 2025 में पुनरुद्धार दर्ज किया, जिसमें सकल एफडीआई अंतर्वाह⁸⁸ वित्त वर्ष 2024 के पहले आठ महीनों में 47.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की समान

अवधि में 55.6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 17.9 प्रतिशत की वृद्धि है।



3.50 लंबी अवधि में, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है, जिससे देश की स्थिति एक सुरक्षित और महत्वपूर्ण वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में मजबूत हुई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)⁸⁹ के आंकड़ों के अनुसार, संचयी एफडीआई अंतर्वाह, जिसमें इक्विटी अंतर्वाह, पुनर्निवेशित अर्जन और अन्य पूँजी शामिल हैं, इस अवधि के दौरान 1,033.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

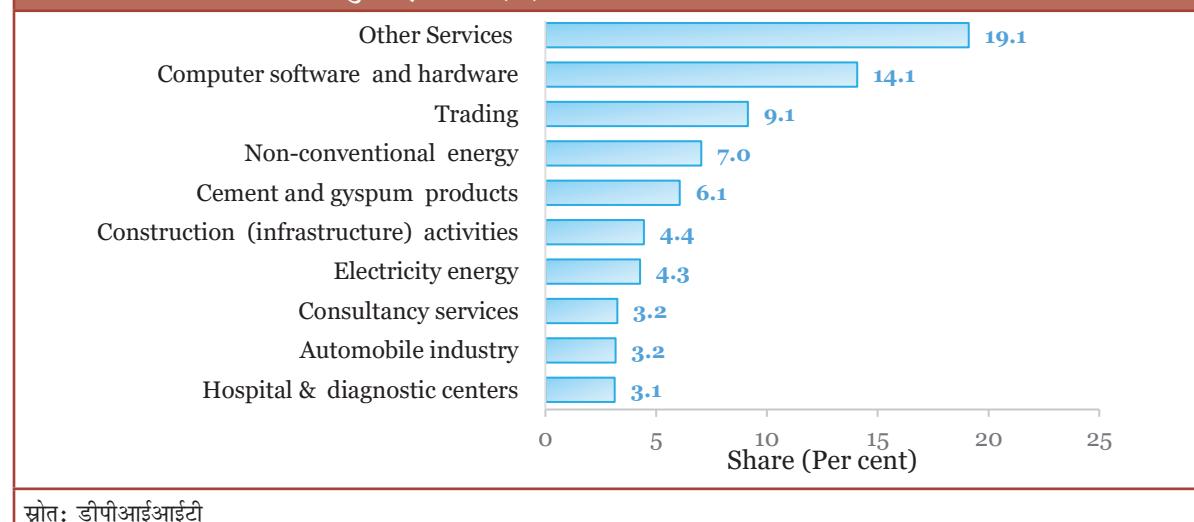
3.51 क्षेत्रीय दृष्टिकोण से, सेवा क्षेत्र⁹⁰ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में कुल इक्विटी अंतर्वाह का 19.1 प्रतिशत था। विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर (14.1 प्रतिशत), ट्रेडिंग (9.1 प्रतिशत), गैर-पारंपरिक ऊर्जा (7 प्रतिशत), और सीमेंट और जिप्सम उत्पाद (6.1 प्रतिशत)⁹¹ शामिल हैं। मुद्रास्फीति के दबाव, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती ब्याज दरों और भू-राजनीतिक तनावों जैसे कारकों से प्रेरित वैश्विक बाजारों में अल्पकालिक अस्थिरता के बावजूद, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अनुकूल बना हुआ है। भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद, चल रहे संरचनात्मक सुधार और बढ़ती उपभोक्ता बाजार स्थिति इसे विदेशी निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाती है।

⁸⁹ एफडीआई प्रवाह पर डीपीआईआईटी की डेटा, <https://tinyurl.com/4hhws2cz>.

⁹⁰ सेवा क्षेत्र में वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय/व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कूरियर, तकनीकी परीक्षण एवं विश्लेषण, अन्य सेवाएं शामिल हैं।

⁹¹ डीपीआईआईटी द्वारा एफडीआई प्रवाह पर क्षेत्रवार डेटा जारी किया जाता है। आरबीआई भारत से एफडीआई प्रवाह के प्रत्यावर्तन/विनिवेश पर डेटा देता है। डीपीआईआईटी डेटा घोषित एफडीआई पर विचार करता है, जबकि आरबीआई का बीओपी डेटा देश में हुए वास्तविक एफडीआई के बारे में जानकारी देता है।

**चार्ट III.15: एफडीआई (वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही) में क्षेत्रीय रुद्धान -
कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में हिस्सेदारीज**



स्रोत: डीपीआईआईटी

3.52 भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हाल ही में घटते अंतर्वाह की चिंताओं के कारण जांच की गई है। हालांकि, व्यापक विश्लेषण⁹² से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ती उधारी लागतों से बाधित हुआ है। भले ही वित्त वर्ष 25 के पहले आठ महीनों में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही प्रत्यावर्तन में भी वृद्धि हुई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को निवेश से रिटर्न मिला है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने द्वितीयक बिक्री और प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से भारत के मजबूत शेयर बाजार का लाभ उठाया है, जो निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। वर्ष 2024 में, भारत के स्थिर व्यापक आर्थिक माहौल और निवेशक-अनुकूल नीतियों के कारण निजी इक्विटी समर्थित निर्गम में तेजी आई। एवेंडस स्पार्क विश्लेषण पर आधारित, डीपीआईआईटी के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से सितंबर 2024 तक भारतीय शेयर बाजारों से निजी इक्विटी और वेंचर कैपिटल एक्सिट (निर्गम) 19.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 18.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक थी।⁹³ भारतीय पूँजी बाजार की गहनता और लचीलापन प्रत्यक्ष निवेशकों के लिए लाभदायक निकास प्रदान करता है, जिससे भविष्य के निवेश को बढ़ावा मिलता है।⁹⁴

3.53 भारत एफडीआई के लिए एक मजबूत गंतव्य बना हुआ है, ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों में उच्च स्थान पर है। हालांकि, देश को संख्याओं पर ध्यान देना होगा। आरबीआई द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 25 के पहले आठ महीनों के दौरान

92 “बिहाइंड इंडियाज ग्रोथ ओवर लास्ट 10 इयर्सखेइंक्रीज इन रिपोर्टिंगशान्स, स्टेडी एफडीआई इन्फ्लोज”। <https://tinyurl.com/2tt3pxsf>.

93 एवेंडस स्पार्क स्ट्रेटेजी-मैक्स अलर्ट- नेट एफडीआई इन्फ्लोज फॉल टू ए रेकॉर्ड लो इन H1 ऑफ FY25

94 <https://www.ft.com/content/0575e216-8dae-4df6-bf50-312f78468e99>.

भारत⁹⁵ में निवल एफडीआई 0.48 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जबकि वित्त वर्ष 24 की इसी अवधि में यह 8.5 बिलियन अमरीकी डॉलर था। इसी तरह, वित्त वर्ष 23 के लिए यह आँकड़ा 19.8 बिलियन अमरीकी डॉलर था। पूरे वित्त वर्ष 24 के लिए, निवल एफडीआई 10.1 बिलियन अमरीकी डॉलर था। पिछले दो वित्तीय वर्षों में वास्तव में भारत से बहुत अधिक प्रत्यावर्तन देखा गया है। वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 में यह राशि क्रमशः 29.3 बिलियन अमरीकी डॉलर और 44.5 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। चालू वर्ष में, नवंबर तक, प्रत्यावर्तन राशि 39.6 बिलियन अमरीकी डॉलर है। इस दर से, पूरे वर्ष का आंकड़ा पिछले वर्ष के आंकड़े से अधिक हो सकता है।

3.54 काफी हद तक यह एक सफलता की कहानी है क्योंकि विदेशी मुनाफा कमाते हैं। दूसरे, इसका अधिकांश हिस्सा पोर्टफोलियो निवेशकों को बेचा गया। दूसरे शब्दों में, वित्त वर्ष 24 में बड़े पोर्टफोलियो अंतर्वाह बड़े प्रत्यावर्तन के सिक्के का दूसरा पहलू थे। सकल स्तर पर, वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 में भारत में प्रतिधारित अर्जन सहित सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में गिरावट देखी गई है। इसने वित्त वर्ष 2014 से देखी गई लगातार बढ़ती प्रवृत्ति को भंग कर दिया है। वित्त वर्ष 2013 और वित्त वर्ष 22 के बीच की अवधि में विकसित देशों में बेहद कम ब्याज दरें और मात्रात्मक सुगम नीतियां देखी गईं। निधियों की लागत काफी कम थी। विकसित देशों में ब्याज दरें 2022 और 2023 में तेजी से बढ़ीं। फेडरल फंड्स रेट 5 प्रतिशत से ऊपर रहा। यूएनसीटीएडी के अनुसार, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे अन्य एशियाई देशों में भी 2023 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में गिरावट देखी गई।

3.55 हालांकि, भारत चालू खाता घाटे में चल रहा है और इसकी अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए इसकी निवेश जरूरतें काफी बड़ी हैं। घरेलू बचत को यथोचित रूप से बड़ी विदेशी बचत के साथ संपूरित करने से पूँजी निर्माण की गुंजाइश बढ़ जाती है। यदि विभिन्न कारणों से पूँजी प्रवाह समस्याग्रस्त होने जा रहा है, तो इससे भारत के लिए सतत चालू खाता घाटे के स्तर के बारे में सवाल उठते हैं। यह पहले की तरह 2.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत नहीं हो सकता है, लेकिन यह काफी कम है। पहले कहा जाता था कि एक देश उतना बड़ा चालू खाता घाटा चला सकता है, जितना शेष विश्व (आरओडब्ल्यू) वित्तपोषित करने को तैयार है। यदि आरओडब्ल्यू विभिन्न कारणों से ऐसा करने में अनिच्छुक या असमर्थ है, तो चालू खाता घाटे का आकार कम करना होगा। विकसित देश भी निवेश को लुभा रहे हैं और भारत अकेले अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है। इसलिए भारत के पास दो विकल्प हैं।

3.56 पहला, हमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने और विदेशी निवेशकों के लिए खुद को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करने होंगे। भारत ऐसा करता आ रहा है। उदाहरण के लिए, देश के अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग से विदेशी निवेशकों के लिए खुले हैं। डाटा में देखा गया बड़ी मात्रा में प्रत्यावर्तन यह भी दर्शाता है कि भारत में किए गए निवेश पर रिटर्न को स्थानांतरित

95 निवल एफडीआई की गणना इस प्रकार की जाती है: -

- (1) विदेशियों द्वारा एफडीआई: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह + प्रतिधारित आय-प्रत्यावर्तन
- (2) भारतीयों द्वारा एफडीआई: विदेशों में भारतीय निवेश+प्रतिधारित अर्जन- प्रत्यावर्तन
- (3) निवल एफडीआई आँकड़ा: (1)-(2)
- (4) इसके पश्चात, पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह हैं: -
- (5) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का निवल प्रवाह - भारतीयों का पोर्टफोलियो निवेश (विदेशों में भारतीयों का पोर्टफोलियो निवेश कम है)
- (6) कुल निवेश प्रवाह: (1)-(2)+(3)

करना आसान है। हालांकि, एपीए (एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट) जैसे मामलों में कर निश्चितता और कर स्थिरता में सुधार की गुंजाइश है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने कई कानूनों, नियमों और विनियमों को सरल बनाया है, जिससे पिछले वर्षों की तुलना में व्यापार करने में आसानी के मामले में शासन में बदलाव आया है। साथ ही, सभी वैधानिक और नियामक प्राधिकरणों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक देशों को क्रॉस-सेक्शनल रूप से बेंचमार्क करते हैं, न कि अनुदैर्घ्य रूप से। यह वैश्विक कंपनियों को भारत में दुनिया के लिए उत्पादन करने के लिए सरकार के लक्ष्य की सफलता का निर्धारण करेगा, जिससे भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन जाएगा।

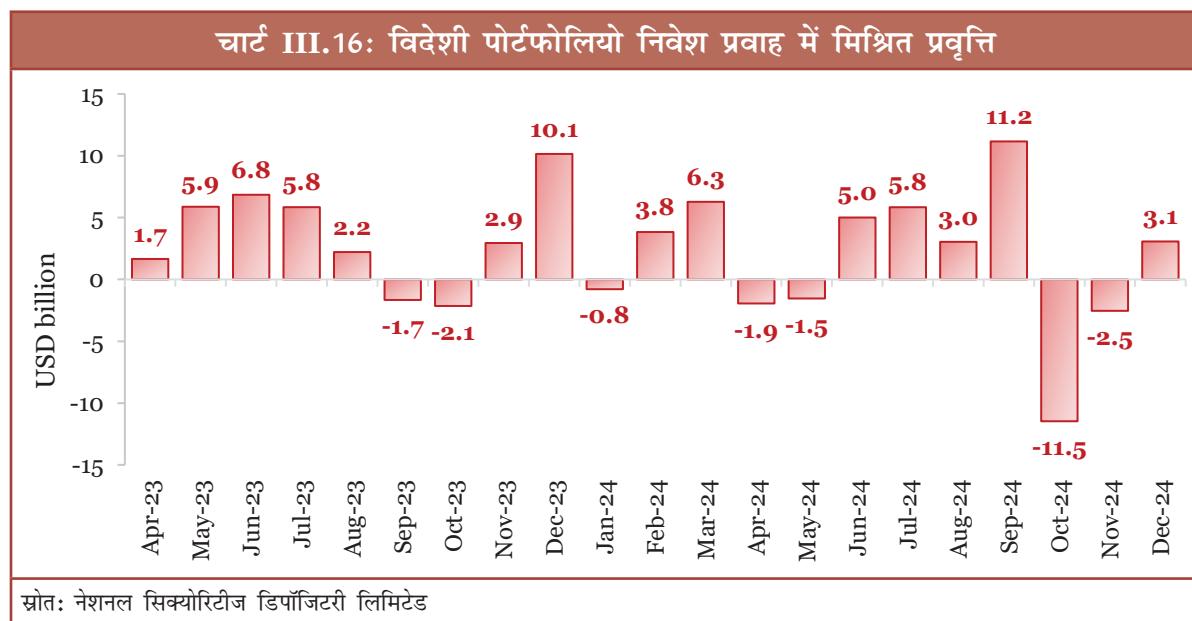
3.57 दूसरा विकल्प उपलब्ध और मौजूदा निवेशों को और अधिक लाभकारी बनाना है। दूसरे शब्दों में, यदि पूँजी बाधाओं के कारण निवेश दर में वृद्धि नहीं की जा सकती है, तो निवेश दक्षता में वृद्धि होनी चाहिए। यहां पर विनियमन और 'कारोबार करने में आसानी' की भूमिका आती है। इसीलिए इस सर्वेक्षण का मुख्य विषय विनियमन के बारे में है। इसमें भारत की निवेश दक्षता में सुधार का सुराग छिपा है। अधिकांश अध्यायों में विनियमनों पर नजर डाली गई हैं और विनियमन की सिफारिश करते हैं। विनियमन विषय पर अध्याय 5 में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है।

पोर्टफोलियो प्रवाह निष्पादन

3.58 एफपीआई वित्त वर्ष 2025 के पहले दो महीनों में विक्रेता होने के बाद जून 2024 से भारतीय इक्विटी बाजार में निवल खरीदार बन गए। यह प्रवृत्ति सितंबर 2024 तक जारी रही, जो भारतीय इक्विटी के लिए स्पष्ट पसंद को दर्शाती है क्योंकि एफपीआई ने उन महीनों में बाजार में पर्याप्त पूँजी लगा दी थी। हालांकि, यह प्रवृत्ति अक्टूबर और नवंबर 2024 की पहली छमाही में उलट गई, जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः 11.5 बिलियन अमरीकी डॉलर और 2.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवल बहिर्वाह हुआ। उपार्जन वृद्धि में मंदी, उच्च मूल्यांकन, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और चीन⁹⁶ में हाल के घटनाक्रमों के बारे में चिंताओं जैसे कारकों ने एफपीआई को भारतीय इक्विटी से महत्वपूर्ण धन निकालने के लिए प्रेरित किया। हालांकि, नवंबर 2024 के उत्तरार्ध के दौरान, एफपीआई भारतीय शेयर बाजार के बारे में अधिक आशावादी हो गए, जिससे अक्टूबर और नवंबर 2024 की शुरुआत में देखी गई महत्वपूर्ण बिक्री उलट गई। एफपीआई अंतर्वाह में यह सकारात्मक प्रवृत्ति दिसंबर 2024 में जारी रही, जिसमें दिसंबर 2024 में निवल प्रवाह 3.1 बिलियन अमरीकी डॉलर था। भारत के मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों, अनुकूल कारोबारी माहौल और मजबूत आर्थिक विकास जैसे कारकों ने निवेशकों को बहिर्प्रवाह की प्रवृत्ति को उलटने के लिए प्रोत्साहित किया है। संचयी आधार पर, भारत में निवल एफपीआई अंतर्वाह⁹⁷ अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 31.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 10.6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। पोर्टफोलियो प्रवाह में अस्थिरता वैश्विक विकास के लिए इक्विटी और बॉन्ड बाजारों की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। हालांकि, भारत में मजबूत आर्थिक और कॉर्पोरेट बुनियादी बातें विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय इक्विटी बाजार के दीर्घकालिक आकर्षण को मजबूत करती हैं।

96 इनमें चीनी सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन उपाय और चीनी शेयरों का सस्ता मूल्यांकन शामिल हैं।

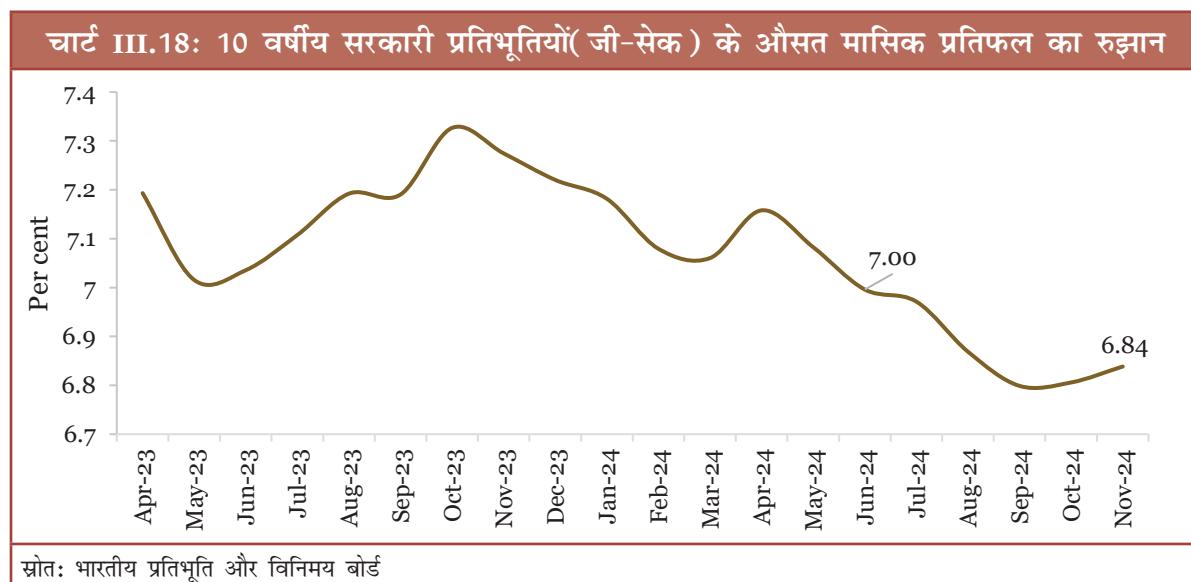
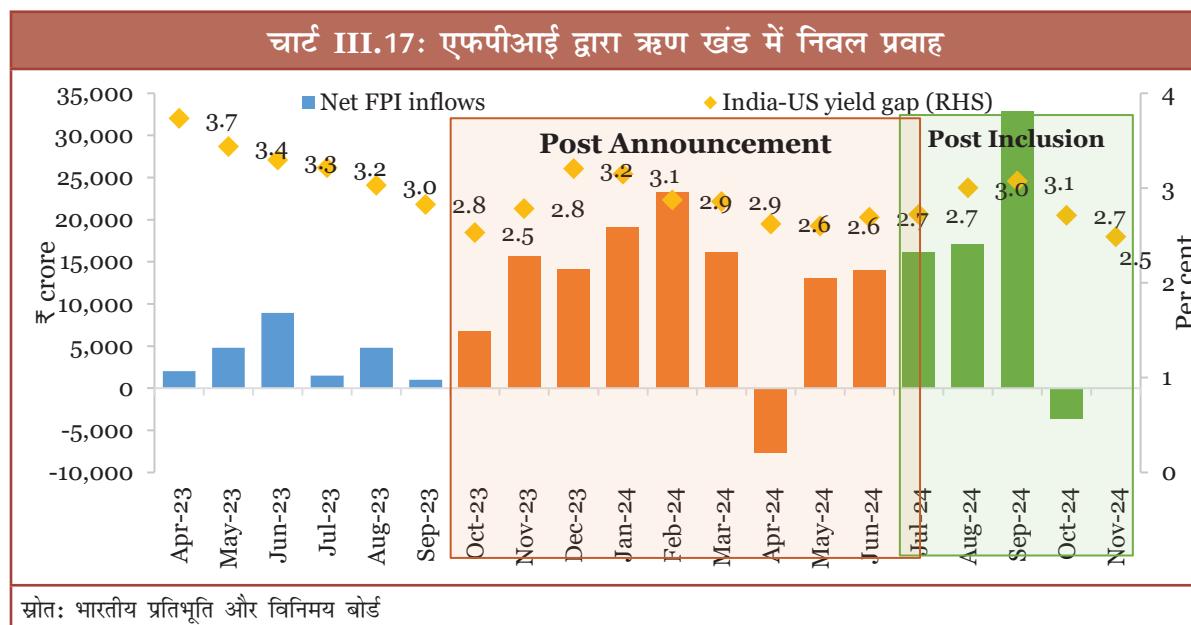
97 निवल एफपीआई अंतर्वाह इक्विटी और ऋण अंतर्वाह का योग है।



3.59 इस वर्ष कई वैश्वक बॉन्ड सूचकांकों में भारतीय सरकारी बॉन्ड (आईजीबी) को शामिल किए जाने से ऋण अंतर्वाह को काफी बढ़ावा मिला है। अक्टूबर 2023 में जेपी मॉर्गन के सूचकांक में शामिल किए जाने की घोषणा के बाद से, अक्टूबर 2023 से जून 2024 तक ₹1.1 लाख करोड़ के संचयी प्रवाह के साथ एफपीआई ऋण खंड में गतिविधि बढ़ गई है। शामिल किए जाने की प्रभावी तिथि के बाद, एफपीआई ने जुलाई से 2024 नवंबर तक ऋण खंड में ₹62,431 करोड़ का निवेश किया। होलिंग्स के कुल बाजार मूल्य को दर्शाने वाली एसेट अंडर कस्टडी (एयूसी) से पता चलता है कि जेपी मॉर्गन ईएम बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किए जाने की घोषणा के नौ महीने के भीतर पूर्णतः अभिगम्य मार्ग (एफएआर) प्रतिभूतियों में एफपीआई का संचयी निवेश 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। वित्त वर्ष 25 में, 15 दिसंबर 2024 तक, समावेशन के परिणामस्वरूप भारतीय एफएआर बांडों में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवल अंतर्वाह हो चुका है, तथा 15 दिसंबर 2024 तक भारत एफएआर बांडों की अभिरक्षा में परिसंपत्तियां 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई हैं।

3.60 चूंकि फेड दरों के प्रक्षेपक्र के बारे में निवेशक के सेंटीमेंट भारत में एफपीआई प्रवाह के प्रमुख चालक हैं, इसलिए भारत और अमेरिका के बीच एफपीआई ऋण प्रवाह और प्रतिफल विभेदक (यील्ड डीफेरेनशियल) के रुझानों का विश्लेषण करना दिलचस्प होगा। चार्ट III.17 भारत और यूएस वर्ष प्रतिफल के बीच एफपीआई ऋण प्रवाह और प्रतिफल विभेदक की तुलना करता है, जो दर्शाता है कि भारत के पक्ष में प्रतिफल विभेदक बढ़ने से अधिक प्रवाह (नवंबर 2023 से मार्च 2024) होता है और इसके विपरीत। मई से जुलाई 2024 तक देखे गए प्रतिफल विभेदक में कमी के बावजूद भारत के मजबूत विकास बुनियादी ढांचे और सीमित मुद्रास्फीति ने इसे विदेशी निवेशकों के बीच पसंदीदा विकल्प बना दिया।⁹⁸

98 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) से प्राप्त इनपुट के आधार पर।



3.61 भारत के सरकारी प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि से सरकार के लिए उधार लेने की लागत कम करने के मामले में सकारात्मक वैदेशिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि बढ़ी हुई मांग और सीमित आपूर्ति गतिशीलता के कारण प्रतिफल में नरमी आई है। इसका प्रारंभिक प्रभाव भारतीय 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में पहले से ही दिखाई दे रहा है। वैश्विक सूचकांकों में भारतीय बांडों को शामिल करने से विदेशी निवेशकों में अपने निवेश पोर्टफोलियो में भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करने की बढ़ती इच्छा, भारत की विकास संभावनाओं में विश्वास और भारतीय बाजारों में वित्तीय स्थिरता का संकेत मिलता है।

अन्य

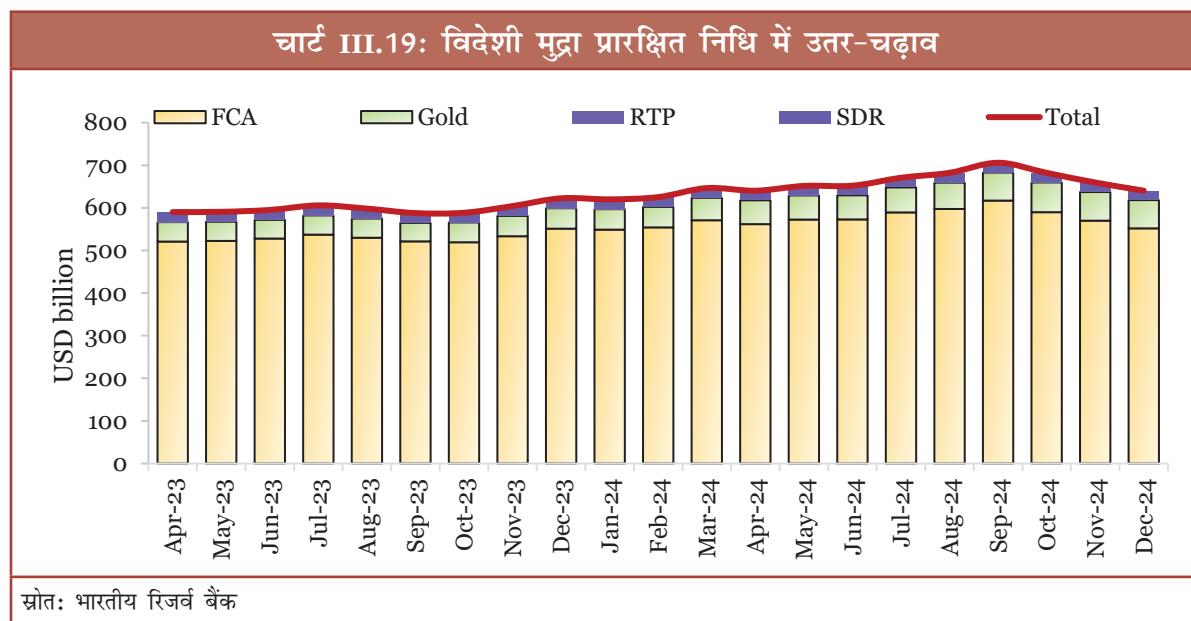
3.62 एनआरआई जमा, विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और अल्पकालिक व्यापार ऋण ने भारत के पूंजी खाते में अतिरिक्त बफर का योगदान दिया है, हालांकि प्रत्येक घटक स्थिरता की अलग-अलग डिग्री प्रदर्शित करता है। ईसीबी हाल के महीनों में प्रक्षेपवक्र ऊपर की ओर दिखाता है, जिसमें अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक निवल प्रवाह बढ़कर 9.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है, जो विदेशी स्रोतों से उधार लेने की अधिक इच्छा को दर्शाता है। इसी तरह, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमा में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही के दौरान निवल प्रवाह बढ़कर 10.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 5.4 बिलियन अमरीकी डॉलर था। इस वृद्धि का श्रेय निरंतर मजबूत धन प्रेषण अंतर्वाह और अनुकूल विनिमय दर परिवेश को दिया जा सकता है, जिसने एनआरआई को भारत में अपनी बचत जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि

3.63 भारत के विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (एफसीए), सोना, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) और आईएमएफ में रिजर्व ट्रेंच स्थिति (आरटीपी) शामिल हैं। 700 बिलियन अमरीकी डॉलर के बेंचमार्क को पार करने के बाद, भारत का विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि दिसंबर 2024 के अंत तक 640.3 बिलियन अमरीकी डॉलर तक कम हो गया है। यह भंडार सितंबर 2024 तक भारत के 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी ऋण के लगभग 90 प्रतिशत को कवर करने के लिए पर्याप्त है, जो बाह्य जोखिम के लिए एक मजबूत स्थिति को दर्शाता है। 2024 तक, भारत ने दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि रखने वाले देशों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, जो चीन, जापान और स्विटजरलैंड के बाद वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। निवल सकारात्मक पूंजी प्रवाह से भारत के विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में 2024 में 27.1 बिलियन अमरीकी डॉलर की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। एफसीए की इस वृद्धि में बढ़ी हिस्सेदारी रही, जिससे भारत की समग्र आरक्षित स्थिति मजबूत हुई।

3.64 आयात कवर, बाहरी क्षेत्र की स्थिरता का एक महत्वपूर्ण संकेतक, दिसंबर 2024 तक 10.9 महीने था। यह वृद्धि भारत की विदेशी झटकों को झेलने की क्षमता को बढ़ाती है, क्योंकि रिजर्व पर्याप्तता उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए आईएमएफ की अनुशासित तीन महीने की आयात कवर से काफी अधिक है।⁹⁹ वित्त वर्ष 24 में 63.7 बिलियन अमरीकी डॉलर का बीओपी अधिशेष, 4.3 बिलियन अमरीकी डॉलर के मामूली मूल्यांकन लाभ द्वारा पूरक किया गया जो इस सुधार का मुख्य चालक था। वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में, विदेशी मुद्रा भंडार 59.4 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़ा, जो 23.9 बिलियन अमरीकी डॉलर के बीओपी अधिशेष और 35.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के मूल्यांकन लाभ से प्रेरित था।

99 आईएमएफ सर्वें: असेसिंग द नीड फोर फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, <https://tinyurl.com/3knsb5se>.



3.65 वैश्विक अनिश्चितता में वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना में उत्तर-चढ़ाव आया है। चालू वर्ष 2024 में सोने की बुलियन होल्डिंग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो मुख्य रूप से उभरते बाजार के केंद्रीय बैंकों¹⁰⁰ द्वारा सोने के संचय से प्रेरित थी। आईएमएफ के अनुसार, वैश्विक रिजर्व प्रणाली में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जिसमें डॉलर के प्रभुत्व से धीरे-धीरे दूर जाना और गैर-पारंपरिक मुद्राओं की बढ़ती भूमिका शामिल है।

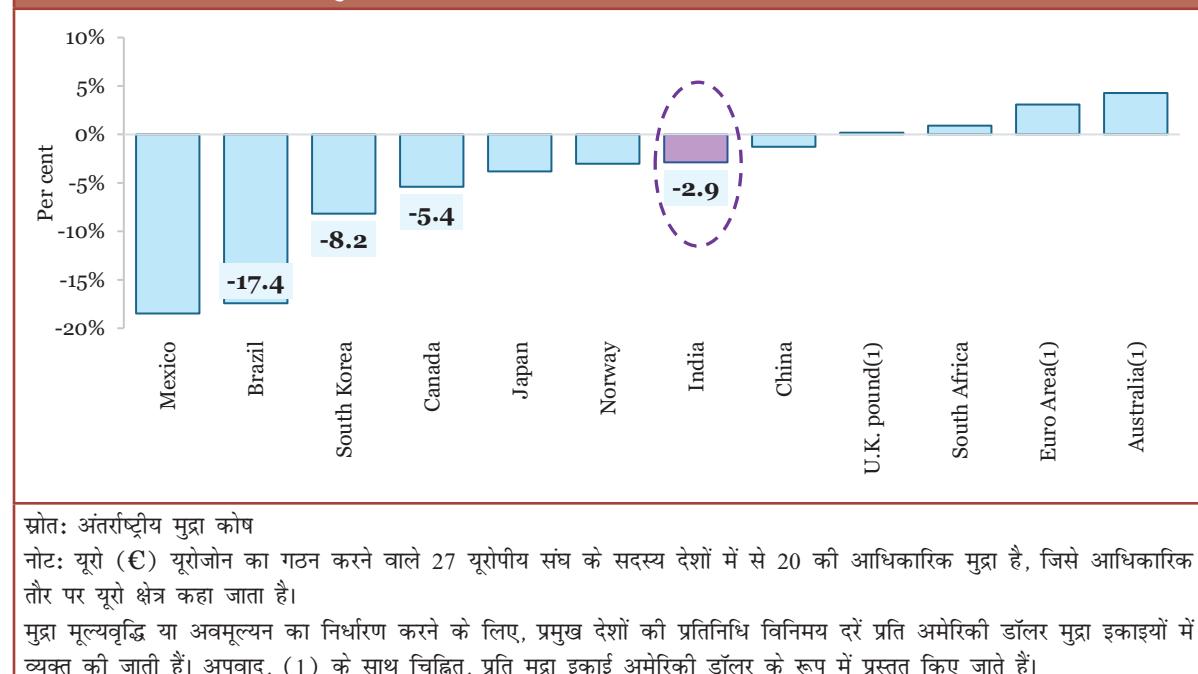
विनिमय दर

3.66 भारतीय रूपये (INR) का मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित होता है, जिसका कोई लक्ष्य या विशिष्ट स्तर या बैंड नहीं होता। विभिन्न घरेलू और वैश्विक कारक भारतीय रूपये की विनिमय दर को प्रभावित करते हैं, जैसे कि डॉलर इंडेक्स की चाल, पूंजीगत प्रवाह में रुझान, व्याज दरों का स्तर, कच्चे तेल की कीमतों में उत्तर-चढ़ाव, चालू खाता घाटा, आदि। वित्त वर्ष 25 के पहले नौ महीनों (06 जनवरी 2025 तक) में, भारतीय रूपये में मामूली 2.9 प्रतिशत की गिरावट आई, जो कि कनाडाई डॉलर, दक्षिण कोरियाई वॉन और ब्राजीलियाई रियल जैसी मुद्राओं से बेहतर है, जो इसी अवधि¹⁰¹ के दौरान क्रमशः 5.6 प्रतिशत, 8.2 प्रतिशत और 17.4 प्रतिशत तक गिर गए। 2024 के दौरान रूपये के मूल्यहास के पीछे प्राथमिक कारकों में से एक मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी चुनाव को लेकर अनिश्चितता के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर का व्यापक रूप से मजबूत होना रहा है।

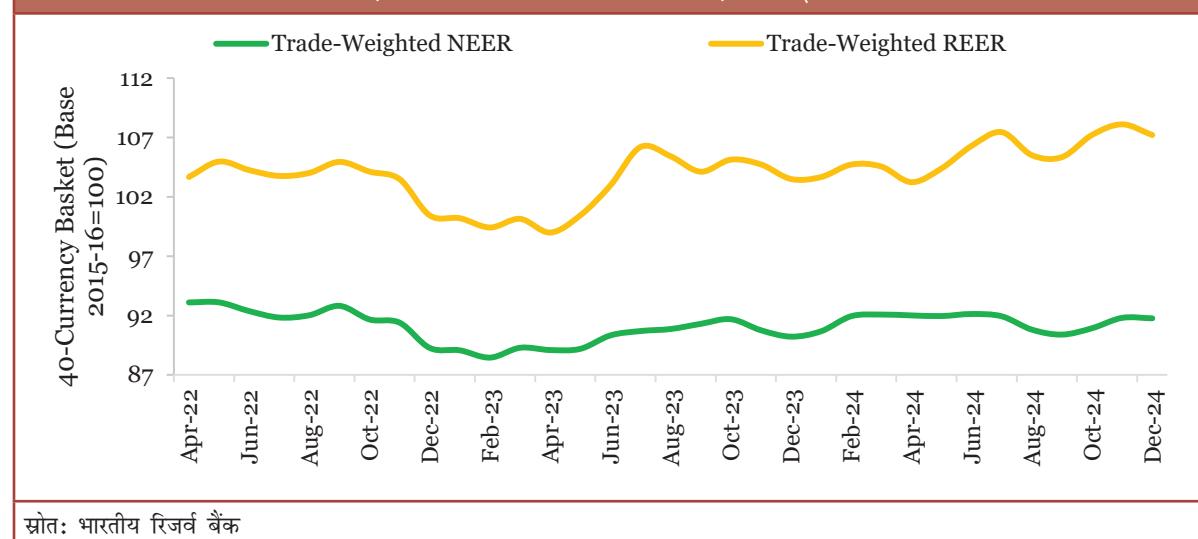
100 आईएमएफ, डॉलर डोमिनेंस इन द इंटरनेशनल रिजर्व सिस्टम: एन अपडेट 2024, <https://tinyurl.com/26dn5sxr>.

101 उपयुक्त नोट 100.

चार्ट III.20: अप्रैल से दिसंबर 2024 तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले प्रमुख देशों की द्विपक्षीय विनिमय दरों में परिवर्तन*



चार्ट III.21: आरईआर (वास्तविक प्रभावी विनिमय दर) और एनईआर (अंकित प्रभावी विनिमय दर) में रुझान

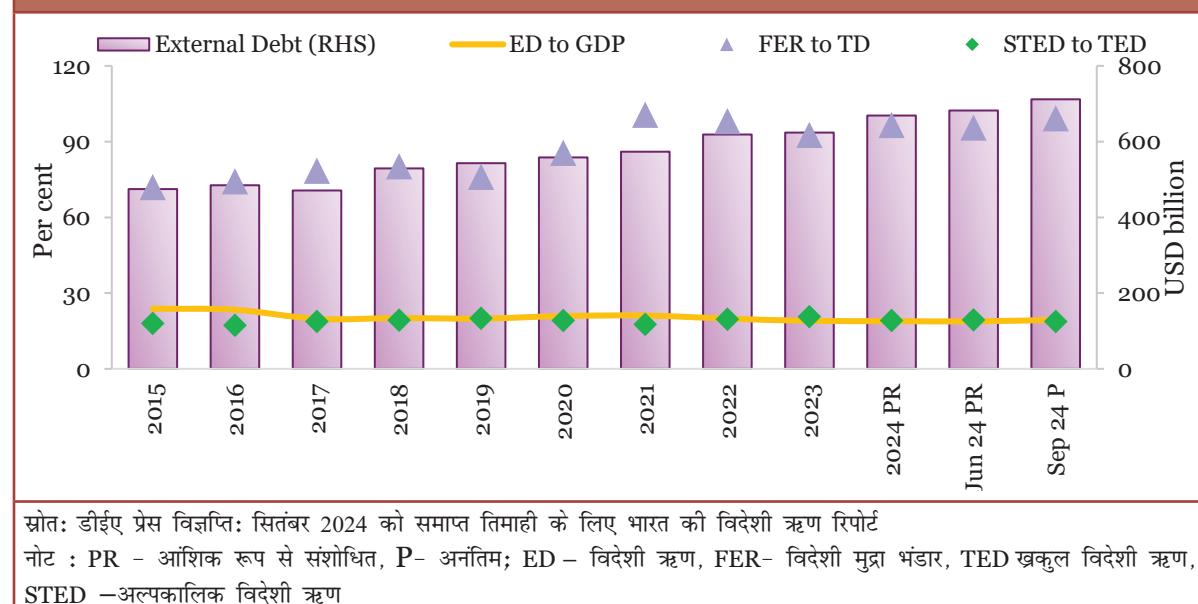


3.67 अस्थिर विनिमय दर व्यवस्था को अपनाने के बाद, प्रभावी विनिमय दरें विदेशी व्यापार योग्य क्षेत्र के सापेक्ष अर्थव्यवस्था के व्यापार योग्य क्षेत्र की विदेशी प्रतिस्पर्धात्मकता का एक प्रमुख उपाय बन गई हैं। भारतीय रूपए के लिए अंकित प्रभावी विनिमय दर (NEER) अप्रैल से दिसंबर 2024 तक 90-92 की सीमा में स्थिर रही, जो विदेशी अनिश्चितताओं के बीच मुद्रा में सापेक्ष स्थिरता को दर्शाता है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER), जो मुद्रा की वास्तविक क्रय शक्ति को दर्शाती है, अप्रैल 2024 में 103.2 से बढ़कर दिसंबर 2024 में 107.2 हो गई।

विदेशी ऋण की स्थिति

3.68 पिछले कुछ वर्षों में भारत का विदेशी ऋण स्थिर रहा है। विदेशी ऋण की स्थिर स्थिति ने वैदेशिक क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखने में मदद की है, खास तौर पर तब जब दुनिया के बाकी हिस्से भू-राजनीतिक प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावित हैं। सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में विदेशी ऋण का अनुपात जून 2024 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 18.8 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर सितंबर 2024 के अंत में 19.4 प्रतिशत हो गया। कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण (एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता के साथ) की हिस्सेदारी जून 2024 के अंत में 19.4 प्रतिशत से सितंबर 2024 के अंत में 18.8 प्रतिशत हो गई। इसी तरह, 13-सभी मुद्राओं में, विदेशी ऋण मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर (53.4 प्रतिशत) में अंकित रहा, इसके बाद भारतीय रुपया (31.2 प्रतिशत), एसडीआर (5 प्रतिशत) और यूरो (3 प्रतिशत) का स्थान रहा।

चार्ट III.22: भारत की स्थिर विदेशी ऋण की स्थिति



दृष्टिकोण

3.69 प्रतिकूल भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारत के विदेशी क्षेत्र ने अच्छा निष्पादन किया है। चालू खाते के मोर्चे पर, हालांकि बाहरी मांग में मंदी के कारण व्यापारिक निर्यात में मध्यम वृद्धि देखी गई है, लेकिन मजबूत घरेलू मांग के कारण व्यापारिक आयात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। बढ़ी हुई निवल सेवा आय और बढ़ते प्रेषण ने व्यापारिक व्यापार घाटे में वृद्धि को कम किया है। पूंजी के मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था में निवल सकारात्मक पूंजी अंतर्वाह देखा जा रहा है। पिछले वर्ष की तदनरूपी अवधि की तुलना में वित्त वर्ष 25 के पहले आठ महीनों में सकल एफडीआई अंतर्वाह में अधिक वृद्धि देखी गई है। हालांकि, प्रत्यावर्तन में उछाल ने निवल एफडीआई में विस्तार पर लगाम लगाई है। वित्त वर्ष 25 के पहले नौ महीनों में एफपीआई अंतर्वाह में उतार-चढ़ाव देखा गया है, जो मिश्रित रुझान दर्शाता है।

3.70 हाल के वर्षों में वैश्विक व्यापार की गतिशीलता में काफी बदलाव आया है, वैश्वीकरण से बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद की ओर, जिसके साथ अनिश्चितता भी बढ़ी है। इसके लिए भारत के लिए एक नई रणनीतिक व्यापारिक रूपरेखा (रोडमैप) की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धी बने रहने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए, भारत को निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए व्यापार लागत को कम करना और सुविधा में सुधार करना जारी रखना चाहिए। व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अच्छी खबर यह है कि ऐसा करना पूरी तरह से हमारे हाथ में है।

3.71 राज्य शासन व्यवस्था करता है और निजी क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं को बनाता है। यदि ये दोनों ही गुणवत्ता और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वैश्विक व्यापार के विस्तार के रास्ते में आने वाले व्यापार तनाव और संरक्षणवाद के बावजूद, भारत विदेशी बाजारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है और पूँजी निर्माण के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए संसाधन उत्पन्न कर सकता है। तब, हमारे लिए निरंतर आधार पर उच्च आर्थिक विकास दर का न केवल सपना देखना बल्कि वास्तव में उसे साकार करना संभव होगा।

यह पृष्ठ खाली छोड़ दिया गया है।